



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

अंतिम जांच परिणाम

**विषय - चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से "पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर" के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच।**

**फा. सं. 14/49/2016-डीजीएडी.—1.** मेसर्स आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स बॉम्बे डाईंग एंड मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता' या 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर (पीएसएफ) (रिसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाईबर अर्थात् केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटारडेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाईबर को छोड़कर)" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/49/2016-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पाटन-रोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की गई, ताकि चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

#### क. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों का पाटन-रोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया है।
- (2) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 2 फरवरी, 2017 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- (3) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत में चीन के दूतावास को जांच शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित कर दिया था कि वह चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों/आयातकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (4) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. मेसर्ज सिक्सी जियांगनान केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
2. मेसर्ज फार ईस्टर्न इंडस्ट्रीज (शंघाई) लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज निंगबो डाफा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
4. मेसर्ज पी.टी. टेईजिन इंडोनेशिया फाईबर कार्पोरेशन टीबीके (टिफिको),  
इंडोनेशिया
5. मेसर्ज पी.टी. इंडोरामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया
6. मेसर्ज पी.टी. सुलिंगाफिन, इंडोनेशिया
7. मेसर्ज पी.टी. ब्रांटा मुलिया टीबीके, इंडोनेशिया
8. मेसर्ज पी.टी. इंडोनेशिया टोरे सिंथेटिक्स, इंडोनेशिया
9. मेसर्ज पेन फाईबर एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
10. मेसर्ज रेकरोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
11. मेसर्ज कांगवाल पॉलिएस्टर, इंडोनेशिया

(5) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई) चीन
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
4. मेसर्ज किसानिन् किंसागलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
5. मेसर्ज किसानिन् एमसी ग्रुप (हांगकांग) कार्पोरेशन लिमिटेड, चीन
6. मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम), चीन
7. मेसर्ज फ्युजियान झेंगकी हाई-टेक-फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, चीन
8. मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड, चीन
9. मेसर्ज पी.टी. इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया
10. मेसर्ज इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
11. मेसर्ज रेकरोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया

(6) बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों की एक अनुपूरक प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे प्राधिकारी को संबद्ध सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान कर दें।

(7) चीन से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी का दावा किया है:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई) चीन
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन

(8) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं।

1. अरविंद लिमिटेड
2. गुलाब फाईबर्स
3. लम्बोधाना टेक्सटाईल्स लिमिटेड
4. मदुरा कोट्स प्राईवेट लिमिटेड
5. रश्मिन लिमिटेड
6. श्री अय्यानार स्पनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड
7. वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड

8. वर्धमान यार्नस एंड थ्रेड्स लिमिटेड

9. वियरिट ग्लोबल लिमिटेड

(9) संबद्ध देशों से निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज बंसवाडा सिंटेक्स लिमिटेड

2. मेसर्ज मदुरा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

3. मेसर्ज अरिवंद लिमिटेड

4. मेसर्ज वर्धमान यार्नस एंड थ्रेड्स लिमिटेड

5. मेसर्ज श्रीश्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स

6. मेसर्ज लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड

7. मेसर्ज वेलस्पन इंडिया लिमिटेड

8. मेसर्ज श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड

9. मेसर्ज आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड

10. मेसर्ज लंबोधारा टेक्सटाईल्स लिमिटेड

11. मेसर्ज सुतलेज टेक्सटाईल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

12. मेसर्ज पी.के.पी.एन. स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

13. मेसर्ज सेंटविन टेक्सटाईल मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड

(10) निम्नलिखित पक्षकारों ने भी याचिका और जांच शुरू करने के खिलाफ कानूनी निवेदन किए हैं:-

1. वर्धमान यार्नस एंड थ्रेड्स लिमिटेड

2. वर्धमान यार्नस एंड थ्रेड्स लिमिटेड

3. अरिवंद लिमिटेड

4. लोंगवालिया यार्न लिमिटेड, लुधियाना

5. विष्णु लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड

6. सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन

7. रूगमिनी राम राघव स्पिनर्स लिमिटेड

8. इंडियन टेक्सपिन्युरर्स फेडरेशन

9. दि साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन

10. साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन

11. सूर्यवंशी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

12. श्री कन्नापिरन मिल्स लिमिटेड

13. सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड

- (11) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों की जांच के प्रयोजनार्थ खुला उपलब्ध कराया गया है।
- (12) इसके अतिरिक्त जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई है। इस जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया है, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया है।
- (13) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे सार्वजनिक फाईल में रखा गया था।
- (14) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उन्हें निर्मित करने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (15) द्वितीयक स्रोत के आयात आंकड़ों (आईबीआईएस के आंकड़ों) के आधार पर याचिका दायर की गई थी। प्राधिकारी ने उसकी जांच की थी और जांच शुरू करने के लिए पाटन और क्षति के पर्याप्त साक्ष्य पाए थे। आईबीआईएस के आंकड़ों को याचिका के एक भाग के रूप में सार्वजनिक फाईल में रखा गया था। जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली और सांख्यिकीय प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी प्रणालियां) से जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार के आंकड़े मांगे थे। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में विभिन्न प्राचलों का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (16) जांच की कार्रवाई 1 अप्रैल, 2015 से शुरू हो कर 30 सितंबर, 2016 (जांच अवधि) तक चली थी। क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच अवधि में अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013-मार्च, 2014, अप्रैल, 2014-मार्च, 2015 और जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।
- (17) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 23.11.2017 को सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में भाग जिन पक्षकारों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को 30.11.2017 तक लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें तथा उसके बाद 07.12.2017 तक उन पर अपने प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत करें।
- (18) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों का निदान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है। संबद्ध देशों के दूतावासों/एसोसिएशनों/परिसंघों/प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए निवेदनों पर विधिवत् विचार किया गया है और उनका उचित रूप से निदान किया गया है।
- (19) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां

प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।

- (20) 10.01.2018 को प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अत्यावश्यक तथ्य निहित हैं। पक्षकारों से कहा गया है कि यदि वे उस पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहते हैं, तो उसे 17.01.2018 तक प्रस्तुत कर दें। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पश्चात प्राप्त हुई टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (21) इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (22) वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 66.53 रूपए है।

#### **ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

##### **घरेलू उद्योग के विचार**

4. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, “0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पालिएस्टर स्टेपल फाईबर (पीएसएफ) (रिसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाईबर अर्थात केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटार्डेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाईबर को छोड़कर)” है।
- (2) संबद्ध वस्तुओं का मुख्यतया प्रयोग 100% पीएसएफ के स्पिन यार्न अथवा प्राकृतिक, कृत्रिम और/अथवा सिंथेटिक स्टेपल फाईबर के रूप में वस्त्रों, सिलाई के धागों, अन्य औद्योगिक वस्त्रों और नॉन-वूवन अनुप्रयोगों आदि के लिए किया जाता है।
- (3) संबद्ध पीएसएफ के तकनीकी विनिर्देशन, उनके डेनियर्स, क्षमता, धुंधले, चमकदार, कम चमकदार, पूर्णतया स्थिर आदि जैसी चमक, रंग, क्रोस-सेक्शन और कट-लेंथ या स्टेपल लेंथ के रूप में वर्णित हैं।
- (4) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है।
- (5) संबद्ध उत्पादों को एचएस संहिता 5503 20 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विभिन्न अन्य एचएस संहिताओं के अंतर्गत भी इन वस्तुओं के आयात किए जाते हैं। यह भी निवेदन किया जाता है कि सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- (6) याचिकादाता कंपनियों ने सूचित किया है कि पाटन मार्जिन के साथ-साथ कीमत संबंधी विश्लेषण (जैसे कि कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री) और सुपर हाई टेनेसिटी (एसएचटी) तथा आधे-धुंधले होने का विश्लेषण, उनकी टेनेसिटी/स्ट्रक्चर के आधार पर पृथक् रूप से किया गया है। ऐसा इस तथ्य के कारण किया गया है कि गैर-विशिष्ट किस्मों के उत्पादों की कीमत में अंतर होता है। तथापि, जहां तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, डेनियर्स, लंबाई, चमक अथवा क्रोस-सेक्शन के कारण उसकी लागत

और कीमत ढांचे में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकादाता कंपनियां, उपरोक्त किस्मों के उत्पादों के आधार पर तुलना किए जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पृथक रूप से विश्लेषण करने के प्रति सहमत हैं।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) विचाराधीन उत्पाद बहुत व्यापक किस्म का है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुविध अनुप्रयोग शामिल हैं, अनुचित रूप से परिभाषित किया गया है
- (2) कीमत प्रभाव और पाटन विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा जानबूझ कर विचाराधीन उत्पाद को सेमी-डल और हाई टेनेसिटी में अनुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।
- (3) वर्तमान जांच में शामिल किए गए “रिसाइकल्ड पीएसएफ, नान-डाइड अथवा डाइड/रंगीन” उत्पाद को स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अपशिष्ट पेट बोटल फ्लेक्स (प्लास्टिक अपशिष्ट) से निर्मित 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर के आयातों को बहिष्करण श्रेणी में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, “0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पालिएस्टर स्टेपल फाईबर (पीएसएफ) (रिसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाईबर अर्थात् केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटारडेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाईबर को छोड़कर)” है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान जांच में अपशिष्ट पेट बोटल फ्लेक्स (प्लास्टिक अपशिष्ट) से निर्मित 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है।

7. उपरोक्त उत्पाद विभिन्न विनिर्देशनों में विनिर्मित किए जाते हैं, जो कि उनके डेनियर्स, क्षमता, चमक (जैसे कि धुंधले, कम चमकदार, चमकदार, पूर्णतया स्थिर आदि) रंग, क्रोस-सेक्शन और कट-लेंथ या स्टेपल लेंथ के रूप में वर्णित हैं। संबद्ध वस्तुओं का मुख्यतया प्रयोग 100% पीएसएफ के स्पिन यार्न अथवा प्राकृतिक, कृत्रिम और/अथवा सिंथेटिक स्टेपल फाईबर के रूप में वस्त्रों, सिलाई के धागों, अन्य औद्योगिक वस्त्रों और नॉन-वूवन अनुप्रयोगों आदि के लिए किया जाता है।

8. प्राधिकारी ने किसी भी पीसीएन अथवा उत्पाद की किस्म को अधिसूचित नहीं किया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने उसका कोई सुझाव दिया है। तथापि, जांच की कार्रवाई के दौरान (डीजीसीआईएंडएस से) आयात के आंकड़ों की जांच करने और घरेलू उद्योग/निर्यातकों द्वारा सत्यापन किए जाने पर यह नोट किया गया था कि संबद्ध वस्तुओं को व्यापक रूप से सेमी-डल पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर और सुपर हाई टेनेसिटी पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी लागत की गहन जांच करने पर यह पता चला था कि दो श्रेणियों के उत्पादों की लागत में अंतर 5% से कम है और इसलिए प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि पृथक पाटन और क्षति विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. विचाराधीन उत्पाद को एचएस संहिता 5503 20 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।

### ग. घरेलू उद्योग का अधिकार-क्षेत्र और आधार

#### घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) भारत में कुल चार उत्पादक कंपनियां नामतः मेसर्ज अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्ज इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड, मेसर्ज दि बंबई डाईंग एंड मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (जो कि याचिकादाता हैं) और मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं, जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं।
- (2) याचिकादाताओं के अतिरिक्त संबद्ध वस्तुओं की एक मात्र अन्य उत्पादक कंपनी मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि मलेशिया में रेकरोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी नामक उत्पादक/निर्यातक से संबंधित है, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। इसलिए मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- (3) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अपात्र उत्पादक है, आवेदक देश में पात्र घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन का 100% भाग बनते हैं।
- (4) आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के आयात नहीं किए हैं। आवेदक संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई संबंध विद्यमान नहीं है, जिससे नियम 2 (ख) के अंतर्गत उनको बहिष्कृत करने की कोई संभावना उत्पन्न होती हो।
- (5) उपरोक्त उत्पादकों के अतिरिक्त भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। याचिका नियमावली के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त आवेदक पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनते हैं।
- (6) हितबद्ध पक्षकारों के ये दावे अनुचित हैं कि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इसलिए घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उससे संबंधित पक्षकार, मेसर्ज रेकरोन ने जांच अवधि के दौरान नगण्य मात्रा में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए हैं। नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उत्पादक की पात्रता की दो शर्तें हैं, अर्थात् उत्पादक का संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक/आयातक के साथ संबंध होना और घरेलू उत्पादक द्वारा आयात किया जाना। वास्तव में प्राधिकारी द्वारा दूसरे भाग के रूप में अर्थात् घरेलू उत्पादक द्वारा आयात किए जाने के संबंध में मात्रा से संबंधित मानदंड को लागू किया गया है। तथापि, यह निवेदन है कि नियम 2 (ख) के स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक/आयातक के साथ घरेलू उत्पादक का संबंध होने के परिप्रेक्ष्य में मात्रा प्रासंगिक मानदंड नहीं है। चूंकि मेसर्ज रेकरोन, मेसर्ज



रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, इसलिए नियम 2 (ख) के अनुसार मेसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना स्वीकार्य नहीं है।

- (7) प्रतिवादी पक्षकारों ने नियमावली के नियम 5 (3) में उल्लिखित स्पष्टीकरण का पूर्णतया गलत प्रतिपादन किया है। नियम 5 (3) के प्रावधान के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे याचिका को 50%+ समर्थन देना अनिवार्य होता हो, विशेषकर जबकि याचिका का कोई प्रतिरोध नहीं है। नियम 5 (3) के प्रावधान के अनुसार याचिकादाता/याचिकादाताओं का देश में संबद्ध वस्तुओं अथवा समान वस्तुओं के कुल उत्पादन में न्यूनतम 25% हिस्सा होना चाहिए। तथापि, याचिका के समर्थन अथवा विरोध में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ नियम में आगे यह व्यवस्था है कि “याचिका का समर्थन करने अथवा उसका विरोध करने” के लिए घरेलू उद्योग का 50%+ समर्थन किए जाने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में याचिका का कोई समर्थन/प्रतिरोध नहीं किया गया है, 50% मापदण्ड की आवश्यकता अमान्य हो जाती है।
- (8) इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन के पेनल के निर्णय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे तर्कों का समर्थन किया गया है कि कुल घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का अंशदान, अनिवार्य रूप से 50% से अधिक होना चाहिए, कानूनी रूप से गलत और असंगत है। पाटन-रोधी करार के परिप्रेक्ष्य में अर्जेन्टीना – पाउटरी के मामले में पेनल ने एक मौके पर यह विचार किया था कि क्या “प्रमुख अंश” शब्दांश का अभिप्राय ऐसे घरेलू उद्योग से होता है, जिसमें घरेलू उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन अधिक बनता है, जो कि कुल घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक होता है। पेनल ने विभिन्न शब्दकोषों में उल्लिखित परिभाषाओं पर विचार किया था और नोट किया था कि शब्द “प्रमुख” को भी “महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष” के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए पेनल ने यह पाया है कि ऐसा प्रतिपादन स्वीकार्य है, जो कि “कुल घरेलू उत्पादन के “महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष अंश के घरेलू उत्पादकों” के रूप में घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है। अर्जेन्टीना – पाउटरी के मामले में पेनल द्वारा किए गए प्रेक्षण निम्नानुसार हैं:-

“7.341. इन विभिन्न शब्दकोषों में उल्लिखित परिभाषाओं पर विचार करते हुए हम नोट करते हैं कि शब्द “प्रमुख” को भी “महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष” के रूप में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, ऐसा प्रतिपादन स्वीकार्य है, जो कि “कुल घरेलू उत्पादन के “महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष अंश को घरेलू उत्पादकों” के रूप में घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है। वास्तव में ऐसा उपागम, अनुच्छेद 4.1 के स्पेनिश रूपान्तर से पूर्णतया सुसंगत है, जो कि उत्पादकों को ऐसे प्रतिनिधि मानता है, जो घरेलू उत्पादन का “यूनो प्रोपोरशियन इम्पोर्टेंट” होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 4.1 “घरेलू उद्योग” को कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अंश के उत्पादकों के रूप में परिभाषित नहीं करता है। यदि अनुच्छेद 4.1 ने प्रमुख अंश को संदर्भित किया होता, तो “घरेलू उद्योग” को ऐसे उत्पादकों के रूप में परिभाषित करने की स्पष्ट आवश्यकता होती, जिनका कुल घरेलू उत्पादन में 50%+ अंशदान बनता है। तथापि, प्रमुख अंश के संदर्भ का तात्पर्य यह है कि “घरेलू उद्योग” को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ एक से अधिक “प्रमुख अंश” हैं। बहुविध “प्रमुख अंश” होने की स्थिति में यह अचिन्तय है कि प्रत्येक विशिष्ट उत्पादक का “प्रमुख अंश” 50% हो सकता है अथवा उससे अधिक होना चाहिए। इसलिए यह हमारे इस निर्णय का समर्थन करता है कि कुल घरेलू उत्पादन के “महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष अंश का उत्पादन करने वाले घरेलू उत्पादकों” के

रूप में घरेलू उद्योग को परिभाषित करना स्वीकार्य है। इन कारणों से हम यह मानते हैं कि पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 4.1 में सदस्यों को "घरेलू उद्योग" के ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका कुल घरेलू उत्पादन में 50%+ अंशदान बनता है।

7.342 रिकार्ड में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे इस मामले की परिस्थितियों का पता चलता हो। कुल घरेलू उत्पादन का 46 प्रतिशत उत्पादन का एक महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा विशेष भाग नहीं हैं। तदनुसार, हम ब्राजील के इस दावे को अस्वीकार करते हैं कि अजेन्टीना ने कुल घरेलू उत्पादन का 46 प्रतिशत उत्पादन करने वाले घरेलू उत्पादकों के रूप में घरेलू उद्योग को परिभाषित करके पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 4.1 का उल्लंघन नहीं किया है (जिस पर बल दिया गया है)।"

- (9) इसके अतिरिक्त पेनल को यूएस – व्हीट ग्लुटेन के सुरक्षा के मामले में एक प्रमुख अंश शब्दांश और डाटा कवरेज के प्रश्न के बीच संबंध की जांच करने का मौका मिला था:

"[करार में विशेष रूप से ऐसा प्रावधान निहित है कि कुछ परिस्थितियों में "घरेलू उद्योग" में ऐसे "घरेलू उत्पादकों" को शामिल किया जा सकता है, जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का सामूहिक उत्पादन, ऐसे उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अंश बनता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरा डाटा कवरेज करना सदैव संभव नहीं होता है और इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि जांच की अधिकतम परिशुद्धता को बनाए रखने के लिए पूर्णतया संभावित डाटा कवरेज की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी किसी विशिष्ट मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें जांच प्राधिकारी को ऐसे कवरेज को प्राप्त करने की अनुमति नहीं हो।]"

- (10) हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के अपर्याप्त आधार होने के तर्कों के आधार पर शुरू की गई इस जांच को समाप्त करने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया है और प्राधिकारी को केवल यह निर्देश दिया है कि वे हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करें और विधि के प्रावधानों के अनुसार मामले में आगे कार्रवाई करें। हितबद्ध पक्षकार जांच की कार्रवाई में परिवर्तन करने के उद्देश्य से विकृत तरीके से मामले के निष्कर्ष को प्रस्तुत करके प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

**12.** घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका को बनाए नहीं रखा जा सकता है और वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकादाता के घरेलू उद्योग बनने के आधार की मुख्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है।
- (2) जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ एक प्रमुख उत्पादक मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया है।
- (3) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जानबूझ कर घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है कि उन्हें कथित रूप से जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियों से पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है।

- (4) मात्र इस आधार पर मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है कि संबद्ध देश में उसका निर्यातक/उत्पादक से संबंध है। ऐसी अवधारणा, प्राधिकारी द्वारा सोडा एश के हाल ही के मामले में लिए गए विचार के विरुद्ध है।
- (5) आवेदक वर्तमान आवेदन-पत्र को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के वास्तविक आधार की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") ने, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है, न तो वर्तमान आवेदन-पत्र को प्रस्तुत किया है और न ही उसका समर्थन किया है।
- (6) मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंधित उत्पादक, मेसर्ज रेकरोन से विचाराधीन उत्पाद के कुल निर्यात न्यूनतम हैं। इसलिए विधि के अंतर्गत मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाहर रखना अस्वीकार्य है।
- (7) यह निवेदन है कि जबकि आवेदकों ने अपने आवेदन-पत्र में यह उल्लेख किया है कि मेसर्ज रेकरोन से संबंधित होने के कारण मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं माना जा सकता है, इसके विपरीत एक आवेदक नामतः मेसर्ज इंडिया रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड ने मेसर्ज पी.टी. इंडोरामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया नामक निर्यातक कंपनी से संबंधित होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि होने के नाते वर्तमान आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।
- (8) यह निवेदन है कि विगत में प्राधिकारी ने स्वतः विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों, विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन और विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग के संबंध में संबंधित निर्यातक से कुल आयातों की मात्रा पर विचार किया है, जब उन्होंने यह निर्धारित करना था कि क्या संबंधित निर्यातक से आयात अत्यधिक है या नहीं ताकि घरेलू उद्योग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक का बहिष्करण करना आवश्यक हो।
- (9) आरआईएल का बहिष्करण करना जिसका भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख भाग बनता है, नियम 2 (ख) (1) (ग) में उल्लिखित परीक्षणों के खिलाफ ऐसे बहिष्करण का परीक्षण किए बिना विधि और न्यायाशास्त्र में पेटेंट त्रुटि है।
- (10) घरेलू उद्योग की परिभाषा में *प्रमुख अंश* शब्दांश के प्रतिपादन के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन अपील निकाय ने चीन से कुछ लौह और स्टील फास्टनर्स पर सुनिश्चित पाटन-रोधी उपाय करने के मामले में दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अपने अंतिम जांच परिणाम में यह पाया था कि यह सिद्ध करते समय कि क्या आवेदक का उत्पादन, विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है, ताकि वह घरेलू उद्योग बन सके, प्राधिकारी को इसकी सावधानी बरतनी चाहिए कि यह क्षति को विकृत करने का वास्तविक जोखिम न शुरू करें। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि घरेलू उत्पादन में निम्नतर भाग होने से जांच प्राधिकारी अधिक संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त भाग पर्याप्त रूप से समग्र उत्पादकों के कुल उत्पादन को प्रतिबिंबित करता है।
- (11) चीन और संयुक्त राज्य अमरीका से ब्रोईलर उत्पादों पर पाटन-रोधी और प्रतिकारी शुल्क उपायों के मामले में विश्व व्यापार संगठन पेनल ने अपने जांच परिणाम में यह नोट किया था कि एक जांच प्राधिकारी को अपने क्षति निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति की अनदेखी करने की अनुमति नहीं है। एक जांच प्राधिकारी परिभाषित घरेलू उद्योग के संदर्भ में अनुच्छेद 3.2 और 3.4 के अंतर्गत अपना विश्लेषण करेगा, लेकिन उसे अपने मूल्यांकन में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति का ऐसा मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता होगी कि क्या संबद्ध आयातों का ऐसा प्रभाव है, जिससे विभिन्न आर्थिक कारकों में परिवर्तन के लिए स्पष्ट

- प्रतिबल पडा है और क्या अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता, परिभाषित घरेलू उद्योग की क्षति का एक संभावित पृथक कारण हो सकती है।
- (12) पाटन-रोधी के अनुच्छेद 5.4 और नियमावली के नियम 5 (3) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक आवेदन-पत्र का समर्थन, ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनका सामूहिक उत्पादन, “समान उत्पाद” के कुल घरेलू उत्पादन का 50% से भी अधिक भाग बनता है, जो कि आवेदन-पत्र का समर्थन अथवा विरोध अभिव्यक्त करते हैं।
- (13) यह निवेदन है कि नियम 5 (3) (ख) में दिया गया स्पष्टीकरण विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि आवेदकों को तभी घरेलू उद्योग माना जाएगा, जबकि आवेदकों का कुल सामूहिक उत्पादन, घरेलू उत्पादकों के समग्र उत्पादन का 50% से अधिक होता है। इसलिए वर्तमान मामले में आवेदकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि घरेलू उत्पादन में उनका अंशदान केवल 43% है, जो कि विधि के अंतर्गत निर्धारित सीमा से काफी कम है।
- (14) निरमा लिमिटेड बनाम सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने यह निर्णय दिया था कि धारा 2 (ख) में संशोधन ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेकाधिकार को समाप्त नहीं किया है। तथापि, पुनःआग्रह किया जाता है कि विद्वान निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया निर्धारण और मौखिक आदेश पारित करते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय आंकड़ों का सही और उचित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है और ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना विधि में निकृष्ट होगी।
- (15) निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर निर्णय लेने का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है और वर्तमान मामले में जिसमें प्रमुख अंशदान अर्थात् 50% से भी अधिक अंशदान ऐसे पक्षकार का है, जो कि एक आयातक के साथ संबंधित हो सकता है, उसे घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि आवेदकों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में उनका अंशदान केवल 43% है। इसलिए आवेदकों ने पहले से ही यह निवेदन किया है कि उनका अंशदान अपेक्षित 50% नहीं है।
- (16) शिकायतकर्ताओं को स्वयं को घरेलू उद्योग सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तीन शर्तों का स्पष्टतया खंडन करना अपेक्षित होता है :-
- (क) वह स्वतः आयातक नहीं हैं – रिलायन्स एक आयातक नहीं है।
- (ख) वह आयातकों से संबंधित नहीं है - रिलायन्स आयातकों से संबंधित नहीं है।
- (17) मेसर्स रेकरोन का भारत में विचाराधीन उत्पाद का तुच्छ निर्यात हुआ है। मेसर्स रेकरोन की निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर का अनुशीलन करने पर यह पता चलता है कि उसने अपनी संबंधित कंपनी, मेसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के घरेलू उत्पादन की तुलना में भारत में स्वतंत्र उपभोक्ताओं को तुच्छ निर्यात किए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मेसर्स रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड भारत में वास्तविक उत्पादक है।
- (18) आयातकों ने रिट याचिका संख्या 17926/2017, 17927/2017 और 17937/2017 दायर करके माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष दिनांक 02.12.2017 की जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय ले लिया है और उनके आदेश के संबद्ध भाग को सुलभ संदर्भ के लिए नीचे पुनःप्रस्तुत किया जाता है:-

“24. यह नोट करना रुचिकर है कि अरूण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में (2007) आई एससीसी 732 में यह सूचित किया गया है कि जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक तथ्य को स्पष्ट किया है, आधिकारिक तथ्य ऐसा तथ्य है, जो कि एक विशिष्ट मामले में न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा एक प्राधिकारी के समक्ष अधिकार-क्षेत्र मानते हुए विद्यमान रहना चाहिए। एक आधिकारिक तथ्य ऐसा तथ्य है, जिसका विद्यमान रहना अथवा नहीं रहना, न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा तथ्य है, जिस पर एक प्रशासनिक एजेंसी की शक्तियां प्रयुक्त होनी निर्भर करती है। यदि आधिकारिक तथ्य विद्यमान नहीं रहता है, तो न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी शक्ति को प्रयुक्त नहीं कर सकता है। यदि कोई न्यायालय अथवा प्राधिकारी ऐसे तथ्य के विद्यमान होने को गलत ढंग से मान लेता है, तो ऐसे आदेश को मानदंड की रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। नीचे दिए गए सिद्धांत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आधिकारिक तथ्य के विद्यमान होने को गलत ढंग से माने जाने पर कोई भी प्राधिकारी स्वतः अधिकार-क्षेत्र मान लेगा, जो कि अन्यथा वह प्राप्त नहीं करता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के आलोक में यदि कोई न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा कोई जांच शुरू करते समय उसके अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी जाती है, तो न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी को ऐसा निर्णय लेना होता है कि क्या वह कार्रवाई करे अथवा नहीं करे और प्रारंभिक अथवा समानान्तर मुद्दे पर निर्णय दे अथवा नहीं, लेकिन ऐसा निर्णय आदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त नियमावली स्पष्ट है, विशेष रूप से सीमा-शुल्क टैरिफ नियमावली का नियम 12 स्पष्ट है और इस न्यायालय के लिए विशेष तरीके से प्रथम प्रतिवादी को कोई निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं है और न ही ऐसा करना उचित होगा क्योंकि वह संबद्ध तथ्यों के आधार पर क्षति का निर्धारण करने के लिए एक सांविधिक शुल्क लगाने के लिए तय है, जिसका निःसन्देह यह तात्पर्य होगा कि क्या पंचम प्रतिवादी को कार्रवाई से बाहर रखा जाए अथवा नहीं। प्रथम प्रतिवादी को यह निर्देश देना पर्याप्त होगा कि वह याचिकादाताओं/एसोसिएशन और विशिष्ट याचिकादाता के साथ-साथ अन्य याचिकादाता सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करे और विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई करे।”

- (19) उपरोक्त आदेश का अनुशीलन करने पर यह पता स्पष्ट चलता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि विद्वान निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रथमतः अधिकार-क्षेत्र के मुद्दे पर स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए, जो कि उक्त बिन्दु को प्रारंभिक मुद्दा बना कर किया जा सकता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

13. पाटन-रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक, मेसर्स आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स बॉम्बे डार्जिंग एंड मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

प्राधिकारी ने याचिका में उल्लिखित तथ्य को नोट किया था कि चतुर्थ उत्पादक, मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड की एक संबद्ध देश में एक संबंधित पक्षकार है और इसलिए वह नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं है। तीन याचिकादाता कंपनियों ने संबद्ध वस्तुओं का न तो कोई आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड में अन्य इंडोरामा कंपनियों के साथ उनके संबंध होने के तथ्य की संपुष्टि, याचिकादाता कंपनियों और साथ ही निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की जांच करने से कर ली गई है। मेसर्ज पी.टी. इंडोरामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया और मेसर्ज इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पीसीएल, थाईलैंड एक दूसरे से संबंधित कंपनियां हैं, लेकिन वे भारतीय याचिकादाता कंपनी, मेसर्ज इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित नहीं हैं।

15. प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी, मलेशिया, मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, जिसकी संपुष्टि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से भी हो गई है। इसलिए उनके बीच संबंध होने का तथ्य पूर्णतया सिद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी, मलेशिया द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरों की जांच डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से करली गई है। मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी, मलेशिया द्वारा किए गए निर्यातों और मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (मी.टन में)	रिलायन्स द्वारा आयातों की मात्रा (कि.ग्राम में)
1	चीन	52,261	743
2	इंडोनेशिया	10,900	-
3	मलेशिया	5,251	-
3 (क)	मेसर्ज रेकरान एसक्यूडीएन बीएचडी द्वारा निर्यात	274	-
4	थाईलैंड	6,867	-
5	संबद्ध देशों के कुल निर्यात	75,279	743
6	अन्य देश	8,901	7,600
7	कुल आयात	84,181	8,343

16. आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट है कि मेसर्ज रेकरोन ने भारत में अंत-प्रयोक्ताओं के साथ-साथ मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चीन से आयात किए हैं। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 2 (ख) के अनुसार अपने अधिकारों के अंतर्गत जांच शुरू करने के समय मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा था।

17. नियमावली के नियम 5 (3) के अंतर्गत की गई जांच के अनुसार याचिकादाताओं की वर्तमान याचिका को दायर करने का स्पष्ट आधार बनता है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग बनने वाले तीन उत्पादकों का अंशदान कुल भारतीय उत्पादन का 49% भाग बनता है और मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अंशदान कुल भारतीय उत्पादन में 51% बनता है, जिसने न तो कोई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और नही याचिका का विरोध किया है। चूंकि याचिका का किसी ने विरोध नहीं किया है, इसलिए तीन उत्पादक नामतः मेसर्ज अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्ज इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्ज दि बंबई डाईंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का स्पष्ट आधार बनता है, जिनके उत्पादन का अंशदान, नियम 5 (3) के अंतर्गत अपेक्षित 25% की पात्र सीमा से अधिक है।

18. जांच शुरू करने के बाद प्राधिकारी को आयातकों/प्रयोक्ताओं से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनुरोध किया गया है कि विश्लेषण के लिए लागत और वित्त से संबंधित आंकड़े मंगाए जाएं और मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के बतौर माना जाना चाहिए क्योंकि क्षति विश्लेषण करने के लिए उसका लागत/वित्तीय आंकड़ों पर प्रभाव पड़ेगा।
19. घरेलू उद्योग की कीमत का परिकलन करते समय मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लागत और वित्तीय आंकड़ों पर विचार करने के लिए आयातकों/प्रयोक्ताओं के विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक पत्र लिख कर उनसे उनके उत्पादन, निर्यातों, आयातों, लागत से संबंधित सूचना और वित्तीय आंकड़े भेजने का अनुरोध किया है। उक्त पत्र के उत्तर में मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उल्लेख किया है कि –
- “चूंकि मलेशिया में एक मात्र निर्यातक, मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी, हमारे पूर्ण स्वामित्वाधीन हमारी एक सहायक कंपनी है। इसलिए हम घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं हैं।*
- तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा मामले को आगे बढ़ाने और आपके द्वारा उस पर कार्रवाई करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।”*
20. इसके अतिरिक्त आंकड़ों की जांच करने पर पता चला है कि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं (जिसके ब्यौर उपरोक्त पैरा में दिए गए हैं)। वर्तमान जांच में चीन एक संबद्ध देश है। इस प्रकार वे नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र हैं।
21. इस स्वीकार्य तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक संबद्ध देश में मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक संबंधित निर्यातक (100% सहायक कंपनी) है और साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी जांच अवधि के दौरान चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं, प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाए और वे नियम 2 (ख) के अनुसार बाकी सभी घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि नियम 5 (3) के अनुसार आवेदकों का स्पष्ट आधार बनता है।
22. याचिका का 50% से अधिक का समर्थन होने की आवश्यकता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों का निवेदन, वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि याचिका का किसी ने कोई विरोध नहीं किया है और घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में याचिकादाता कंपनियों का अंशदान लगभग 43% है।
23. जैसा कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने उद्धृत किया है, वर्तमान मामले में विश्व व्यापार संगठन के न्यायाशास्त्र को नोट कर लिया गया था और यह पाया है कि वर्तमान मामले में आधार कानूनी है और पूरी सावधानी के साथ उसे प्राप्त किया गया है। इसी फास्टनर्स में अपील निकाय की रिपोर्ट में जिस पर हितबद्ध पक्षकारों ने विश्वास किया है, मात्र यह उल्लेख है कि “एक प्रमुख भाग”, कुल घरेलू उत्पादन का पर्याप्त भाग प्रतिबिंबित होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि “प्रमुख भाग”, स्वतः कुल उत्पादन होना चाहिए अथवा कुल उत्पादन के नजदीक होना चाहिए। इसी मामले में अपील निकाय ने यह भी चेतावनी दी है कि “जितना कम भाग होगा, वह उतना ही संवेदी होगा”। प्राधिकारी को यह अधिक सुनिश्चित करना होगा कि प्रयुक्त भाग, समग्र उत्पादकों के कुल उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करे। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां तक यह सुनिश्चित करना है कि यह कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है, निम्नतर भाग भी अनुच्छेद 4.1 (ग) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

24. माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के निर्णय को बारीकी से समझा गया है और यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को कोई निर्देश जारी नहीं करने का निर्णय लिया है और यह प्राधिकारी पर छोड़ दिया है कि वे संबद्ध नियमावली के अनुसार संबद्ध तथ्यों के आधार पर क्षति का निर्धारण करें। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल प्राधिकारी को यह निर्देश देना ही पर्याप्त समझा है कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करें, जिसका प्राधिकारी द्वारा 23.11.2017 को मौखिक सुनवाई करके विधिवत् अनुपालन किया गया है, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को भाग लेने का निमंत्रण दे कर उन्हें अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने और बाद में उसे लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। ऐसी मौखिक सुनवाई करने के अवसर का सभी हितबद्ध पक्षकारों ने व्यक्तिगत रूप से और/अथवा अपने कानूनी प्रतिनिधियों/एसोसिएशनों के माध्यम से लाभ उठाया है।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने जांच करने के बाद यह निर्णय लिया है कि याचिकादाता कंपनियां, नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनती हैं। इसके अतिरिक्त नियम 5 (3) के अनुसार याचिकादाता कंपनियों का वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है।

### **घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

26. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता ने केवल ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता की अनुमति, नियमावली के अंतर्गत और प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार दी गई है।
- (2) याचिकादाता ने आवेदन-पत्र का उचित अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान किया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार ऐसी कोई भी विशिष्ट सूचना का उल्लेख नहीं कर पाया है, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है और जो कि नियमावली के अंतर्गत यथोचित नहीं है।
- (3) भारत में निर्यातों की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्रियों की सकल मात्रा, उत्पादन, बिक्रियों, भारत में निर्यातों की औसत कीमत की सूचना, सूचीबद्ध रूप में प्रदान की गई है क्योंकि ऐसी सूचना व्यावसायिक स्वामित्व सूचना होती है और इसलिए यह गोपनीय प्रकृति की होती है।
- (4) किसी भी निर्यातक ने अपने उत्तर में ऐसा कोई अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि उनके गोपनीय वृत्तान्त की सही प्रतिकृति हो। उन्होंने समस्त मात्रा संबंधी सूचना को गोपनीय रखा है। उन्होंने गोपनीयता के दावे का कोई विवरण भी प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उनके उत्तर, निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों के अगोपनीय वृत्तान्त को प्रस्तुत करने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन भी है। इसलिए घरेलू उद्योग का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों की अनदेखी करें और साथ ही निर्यातकों के उत्तरों को अस्वीकार भी करे और उन्हें कोई विशिष्ट पृथक दर्जा भी नहीं दें।

#### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

27. वर्तमान जांच की कार्यवाई के दौरान गोपनीयता के बारे में उत्पादकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका में अत्यधिक गोपनीयता रखी गई है। इसके अतिरिक्त याचिका में मात्रा संबंधी कोई सूचना भी निहित नहीं है।



(2) घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसे अत्यधिक गोपनीयता बरतने की अनुमति भी दी गई है कि उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट को भी सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध नहीं कराया है।

(3) इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने अपनी लागत संबंधी सूचना भी प्रदान नहीं की है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है, जिसमें नियम 6 (7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त, उनकी जांच के लिए निहित है।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

### **ड. विविध मुद्दे**

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

30. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्रतिवादी उत्पादकों ने उत्पादन, बिक्रियों और इनपुट की अधिप्राप्ति में लगे अपने संबंधित पक्षकारों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना को छिपाए रखा है। इसलिए उनके उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कोई विशिष्ट पृथक मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
- (2) संबद्ध वस्तुएं यार्न की कुल लागत का लगभग 45-50% भाग बनती हैं, जिसे बाद में शिफ्टिंग, सूटिंग और अन्य परिधानों में प्रयुक्त किया जाता है। तैयार माल की लागत के साथ तुलना करने पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव तुच्छ होता है, अर्थात् संबद्ध वस्तुओं पर 10% का शुल्क लगाने से फैब्रिक की लागत में यह शिफ्टिंग के मामले में 0.57 - 1.3% और सूटिंग के मामले में 1.2 - 2.3% होगा।

#### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

31. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाताओं द्वारा दायर की गई याचिका, विश्वसनीय और गलत आंकड़ों पर आधारित है।
- (2) जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि होने का कारण याचिकादाताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के मुद्दे हैं।
- (3) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में साक्ष्य की कमी होने के साथ-साथ विधि के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की भी कमी है और इसलिए उसे वैध तथा पूर्णतया प्रलेखित आवेदन-पत्र नहीं माना जा सकता है। पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे तब तक पाटन-रोधी जांच की शुरुआत नहीं करें, जब तक कि (क) यह निर्धारित नहीं

हो जाता है कि आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है और (ख) वे आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की परिशुद्धता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेते हैं तथा जांच की शुरुआत को यथोचित ठहराने के लिए वे स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। इसका निर्धारण करना कि आवेदन-पत्र, समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा ऐसी दशाएं विद्यमान हैं, जो कि जांच शुरू करने से पहले पूरी की जानी आवश्यक हैं।

- (4) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन-पत्र में अवास्तविक और अविश्वसनीय आयात आंकड़े प्रयुक्त किए हैं।
- (5) एक्सल फाईल में आयात आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने आईबीआईएस से प्राप्त किए गए मूल/अपरिष्कृत कारोबार-वार आयात के आंकड़ों की प्रति भी प्रदान नहीं की है।
- (6) यदि पीएसएफ पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो पीएसएफ पर 5% शुल्क लगाए जाने से कीमत में लगभग 5 रूपए की वृद्धि होगी और 10% शुल्क लगाए जाने से कीमत में लगभग 10.5 रूपए की वृद्धि होगी, जिससे यार्न उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यार्न की लागत अप्रभावित रहेगी, इसलिए शुल्क लगाने से केवल भारतीय बाजार पर प्रभाव पड़ेगा और यार्न उद्योग को शुल्क लागू करने का बोझ उठाना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप समग्र भारतीय उद्योग पर अतिरिक्त लागत आएगी और उसका बोझ उठाना पड़ेगा और यह पीएसएफ अथवा विचाराधीन उत्पाद तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रपाती प्रभाव उद्योग पर भी पड़ेगा।
- (7) संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग, घरेलू उद्योग के उत्पादन से अधिक है। इस प्रकार आयात अपरिहार्य हैं।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

32. विविध निवेदनों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

- (1) यह तर्क निराधार और यह गैर-प्रमाणित है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका गलत आंकड़ों पर आधारित है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के बारे में संतुष्ट होने पर जांच शुरू की थी और प्राधिकारी प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। प्राधिकारी ने ऐसे आंकड़ों/सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर जांच शुरू की थी, जो कि नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने के लिए यथोचित थे। इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।
- (2) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पादों के संबंध में गुणवत्ता के मुद्दों के कारण जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह तर्क गैर-अधिप्रमाणित है। तथापि, प्राधिकारी ने पहले से ही यह विचार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही वस्तुएं और आयातित वस्तुएं "समान वस्तुएं" हैं और वे समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने सुसंगत रूप से यह माना है कि पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ स्वतः गुणवत्ता एक निश्चयात्मक कारक नहीं है।

- (3) आयात आंकड़ों (डीजीसीआईएंडएस) के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात आंकड़ों की एक प्रति सार्वजनिक फाईल में रखी गई थी, जो कि हितबद्ध पक्षकारों की जांच के लिए उपलब्ध थी और रिकार्ड से यह पता चलता है कि अधिकतर हितबद्ध पक्षकारों ने अपने रिकार्ड के लिए आंकड़ों की प्रति प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी की यह सुसंगत पद्धति रही है कि हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें आयात के आंकड़ों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी से आयात के आंकड़ों की प्रति प्रदान करने का कोई अनुरोध नहीं किया है।
- (4) आईबीआईएस के आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईबीआईएस के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका का एक भाग थे। याचिका की एक सॉफ्ट प्रति, सभी सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर प्रदान की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों की जांच के लिए याचिका की एक प्रति सार्वजनिक फाईल में भी रखी गई थी। इसलिए वर्तमान मुद्दे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क निराधार हैं।
- (5) घरेलू उद्योग ने निचले स्तर के उद्योग पर पाटन-रोधी शुल्क के प्रभाव के लिए विस्तृत परिकलन प्रदान किए हैं और यह नोट किया जाता है कि यह प्रभाव अत्यधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य उचित व्यापार सुनिश्चित करना और घरेलू उद्योग को समान व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना है।
- (6) जांच अवधि (18 महीनों) के दौरान कुल मांग 1,209,242 मी.टन है, जो कि कुल घरेलू बिक्रियों (आवेदकों और अन्य) और कुल आयात (संबद्ध देश और अन्य देश) का योगफल है। भारत में कुल संस्थापित क्षमता, वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों को बाधित करना नहीं है, बल्कि निर्यातकों और घरेलू उद्योग के लिए उचित और समानान्तर व्यापारिक क्षेत्र सृजित करना है।

#### **च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

##### **सामान्य मूल्य**

##### **घरेलू उद्योग के विचार**

33. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 8 के अनुसार चीन को तब तक एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, जब तक कि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक, पैरा 8 (3) में उल्लिखित मानदंड के आधार पर उक्त पूर्वधारणा का खंडन नहीं करते हैं। यह विगत मामलों में प्राधिकारी द्वारा तथा अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई पद्धति के समनुरूप है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग का विनम्रता पूर्वक यह अनुरोध है कि चीन को निम्नोक्त कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए:-
  - (क) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें, पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।

- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थितियों में अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जिनमें चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हैं कि उनकी लेखा बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों (आईएस) के समनुरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करने पर जोर देने की आवश्यकता, वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्व और व्यय, परिसम्पतियों और देयताओं की परिशुद्धता और पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है।
- (ग) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक प्राचल के संबंध में जांच को पूरा नहीं कर देते हैं। इसके विपरीत वास्तविक क्षति की जांच करते समय एकल प्राचल का विद्यमान होना ऐसी क्षति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। अन्य शब्दों में जहां एक प्राचल क्षति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है, वहां एकल प्राचल का जांच में विफल रहना, बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।
- (घ) यह सिद्ध करना प्राधिकारी का दायित्व नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां, बाजार अर्थव्यवस्था के परिवेश में प्रचालन कर रही हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण की हकदार हैं। लेकिन यह दायित्व चीन के निर्यातकों का है कि वे यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।
- (ङ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रतिवादी कंपनियां और उनका समूह समग्र रूप से उसका दावा नहीं करते हैं। यदि किसी समूह में शामिल एक कंपनी अथवा अधिक कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, तो उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (च) यह निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, नियम 8 (2) के परन्तुक को लागू किए बिना केवल पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (छ) इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण, (क) भारत में तृतीय देशों से आयात कीमत, (ख) भारत में बिक्री कीमत और (ग) भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को विधिवत् समायोजित किया जाना चाहिए। यह भी निवेदन किया जाता है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए यह विकल्प उपलब्ध हैं, प्राधिकारी कृपया “किसी अन्य आधार” पर भी विचार कर सकते हैं क्योंकि इसे तभी लागू किया जा सकता है, जब विधि में सूचीबद्ध अन्य आधार लागू नहीं किए जा सकते हों।
- (ज) केवल मेसर्स फ्यूजियान जिंगवेल, मेसर्स जिआंगियान हुआहोंग और मेसर्स जिआंगियान हेलुन नामक निर्यातकों ने एमईटी के दर्जे का दावा किया है, जो कि पूरा नहीं है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता है। चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकृत करने के लिए उसकी प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं किया है।
- (झ) चीन के निर्यातकों ने संबंधित पक्षकारों और कंपनी के शेयरों से संबंधित सूचना को भी छिपा कर रखा है और ऐसी सूचना निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कंपनी के एमईटी के दावे को अस्वीकार कर दें।

- (ज) चीन से प्रतिवादी उत्पादकों ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदान नहीं की है क्योंकि चीन में उनके संबंधित प्रयोज्यताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- (ट) चीन से प्रतिवादी /निर्यातकों ने चीन सरकार से उन्हें प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के बारे में सुगमता से कोई सूचना प्रदान नहीं की है। चीन के उत्पादकों का तुलन पत्र और फाईन डेनियर पीएसएफ के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा की गई जांच से स्पष्ट पता चलता है कि चीन के उत्पादकों ने चीन की सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त किया है। चीन के उत्पादकों द्वारा ऐसी प्रमुख सूचना प्रदान नहीं करना प्राधिकारी को भ्रमित करने जैसा है और उनके द्वारा प्रदत्त समस्त सूचना संदेहास्पद प्रतीत होती है। इसलिए पूरी और सही सूचना नहीं होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (ठ) अनुबंध-1 का पैरा 8 निर्दिष्ट प्राधिकारी को सिवाए यह मानने के लिए कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, कोई और विकल्प नहीं देता है। तथापि, पैरा 8 (3) के प्रावधान के अंतर्गत चीन की फर्मों को ऐसी अवधारणा का खंडन करने का विकल्प प्राप्त है।
- (ड) निर्दिष्ट प्राधिकारी संविधि के सृजनकर्ता हैं और उन्हें संविधि के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए जब तक पैरा 8 में संशोधन नहीं कर दिया जाता है, तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे पैरा 8 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करें और चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानें।
- (ढ) चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का निरंतर अत्यधिक अन्तःक्षेप होने के कारण चीन को गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने की आवश्यकता है। यह ज्ञात तथ्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर राज्य प्रतिबलों का नियंत्रण है और देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के तंत्र का अत्यधिक अन्तःक्षेप है और नियंत्रण है। विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगमन के अंतर्गत बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत करना स्वचालित नहीं है, बल्कि यह अभिगमन नयाचार में उल्लिखित पूर्वशर्तों का चीन द्वारा अनुपालन किए जाने पर प्रासंगिक है।
- (ण) इंडोनेशिया के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक, मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया ने अपने संबंधित पक्षकारों, शेयरहोल्डिंग्स और कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में अपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। उसने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली अपनी संबंधित कंपनियों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। उसकी वेबसाइट से यह स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी की मेसर्ज पीटी इंडो-रामा पेट्रोकेमिकल्स नामक एक संबंधित कंपनी है, जो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कच्चे माल, प्यूटरीफाईड टेरेफिथेलिक एसिड विनिर्मित करती है। मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदान नहीं की है क्योंकि उसके संबंधित प्रयोज्यताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उनके उत्तर को अस्वीकार कर दें और विशिष्ट पृथक पाटन/क्षति मार्जिन के लिए उन पर विचार नहीं करें।
- (त) थाईलैंड के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक, मेसर्ज इंडो-रामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदान नहीं की है क्योंकि उसके संबंधित प्रयोज्यताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है। प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक, मेसर्ज इंडो-रामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर से यह स्पष्ट पता

चलता है कि उसने अपने संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल की खरीद की है। उसने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली अपनी संबंधित कंपनियों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई लागतों आदि से संबंधित सूचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उनके उत्तर को अस्वीकार कर दें और विशिष्ट पृथक पाटन/क्षति मार्जिन के लिए उन पर विचार नहीं करें।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

34. चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किए हैं और निवेदन किए हैं:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई) चीन
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
4. मेसर्ज किसानिन् किंसागलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
5. मेसर्ज किसानिन् एमसी ग्रुप (हांगकांग) कापॉरेशन लिमिटेड, चीन
6. मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम), चीन
7. मेसर्ज फ्युजियान झेंगकी हार्ड-टेक-फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, चीन
8. मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड, चीन
9. मेसर्ज पी.टी. इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया
10. मेसर्ज इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
11. मेसर्ज रेकरोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया

35. निम्नलिखित पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा किया है:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई) चीन
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन

36. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण के अपने दावों के अतिरिक्त पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि दिसंबर, 2016 को समाप्त हुए और उस तारीख के बाद विश्व व्यापार संगठन के साथ चीन जनवादी गणराज्य के अभिगमन के नयाचार की धारा 15 (क) (ii) के अनुसार भारत को विश्व व्यापार संगठन के करारों के अंतर्गत अब कोई कानूनी आधार प्राप्त नहीं है कि वह टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद-4 और अन्य शामिल करारों के क्रियान्वयन पर करार की गैर-आवश्यकताओं को प्रयुक्त करते हुए चीन के उत्पादों की पाटन-रोधी जांच में सामान्य मूल्य का परिकलन करे।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

37. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना प्रदान करें। संबद्ध देशों से अनेक उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

38. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में यह आरोप लगाया है कि चीन की कंपनियां निरंतर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रही हैं। घरेलू उद्योग के इस दावे के आधार पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने की अधिसूचना का उत्तर दें और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने के लिए ऐसी संबद्ध सूचना प्रस्तुत करें, जिससे ऐसा प्रदर्शित होता हो कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं। प्राधिकारी ने पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए चीन में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया था कि वह अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे सभी संबद्ध सूचना प्रदान करें।

39. चीन से निम्नलिखित उत्पादकों के साथ उनके कुछ निर्यातकों/व्यापारियों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई)
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड के साथ उसके व्यापारी, मेसर्ज यूनाईटेड राॅ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
4. मेसर्ज किसानिन क्विंगगुलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
5. मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम) के साथ उसके व्यापारी, मेसर्ज यूनाईटेड राॅ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड और मेसर्ज किसानिन एमसी ग्रुप (हांगकांग) कार्पोरेशन लिमिटेड
6. मेसर्ज फ्युजियान झेंगकी हाई-टेक-फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड

40. चीन से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुपूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए थे:-

1. मेसर्ज फ्युजियान जिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड (जिंगवेई) चीन
2. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन
3. मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन

41. जांच शुरू होने के पश्चात् घरेलू उद्योग ने एक अन्य प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि चीन की कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन नहीं कर रही हैं और चीन के बाजार में सरकार का अत्यधिक नियंत्रण है। इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए उनकी लागत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

42. प्राधिकारी ने चीन की ऐसी प्रतिवादी कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचना को संज्ञान में लिया है, जिन्होंने एमईटी की अनुपूरक प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिनमें उन्होंने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अनुसार ऐसी अवधारणाओं का खंडन करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी कंपनियां यह सिद्ध करने के लिए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रही हैं, पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही हैं।

43. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रतिवादी कंपनियों ने अपनी धारक/सामूहिक कंपनियों, कच्चे माल के स्रोत, विनिमय दरों की विश्वसनीयता और अन्य संबद्ध सूचना के संबंध में अपने उत्तर में पर्याप्त व्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनसे यह सिद्ध हो सके कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर

रही हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन की उपरोक्त प्रतिवादी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दर्जा स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।

44. इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन करता हुआ नहीं पाया गया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी, चीन की उपरोक्त कंपनियों पर नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं और प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी अपेक्षित है।

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तृतीय देश की लागतों और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्रियों अथवा तृतीय देश की निर्यात बिक्रियों के साथ-साथ तृतीय देश में ऐसे उत्पादकों के उत्पादन की लागत के संपूर्ण और व्यापक आंकड़े और उनके सहयोग की आवश्यकता है। इन बाजारों में कीमतों और लागतों के संबंध में ऐसी कोई सूचना विद्यमान नहीं है, जिसे आवेदक अथवा प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई हो और न ही ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने इस चरण में तृतीय देश की उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई दावा भी नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य संरचित करने की कार्रवाई करते हैं।

46. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परन्तुक के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है। तदनुसार, उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए कार्यगत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों और लाभ को शामिल करने के लिए उचित समायोजन किया जाना है। इस प्रकार से संरचित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **I. चीन जनवादी गणराज्य के मामले में निर्यात कीमत**

##### **मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड**

47. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के 4376 मी.टन निर्यात किए हैं, जिनमें से \*\*\*मी.टन सीधे और \*\*\*मी.टन निर्यात, मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल मलेशिया (\*\*\* मी.टन) और मेसर्ज त्रिवेणी स्पिनिंग मिल, नेपाल (\*\*\* मी.टन) नामक उससे गैर-संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए हैं। उसके बदले में मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल मलेशिया ने भारत में (\*\*\* मी.टन) सीधे निर्यात किए हैं और बाकी (\*\*\* मी.टन) निर्यात, मेसर्ज एस्ट्रेल ऑवरसीज प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर नामक अन्य व्यापारिक कंपनी द्वारा किए गए हैं, जिसने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

48. प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर की जांच की है और यह नोट किया है कि भारत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अधिकतर निर्यातों के लिए उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसी मात्रा को स्वीकार किया है, जिसके लिए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात व्यौरों पर विचार किया गया है। निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, विदेशी भाड़े, बैंक प्रभारों, क्रेडिट के



लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

संरचित सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
***	***

### **मेसर्ज फ्युजियान जिनुलुन फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड**

49. मेसर्ज फ्युजियान जिनुलुन फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज फ्युजियान जिनुलुन फाईबर शेयरहोल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं, जिनमें से \*\*\*मी.टन सीधे और \*\*\*मी.टन निर्यात, मेसर्ज यूनाईटेड राँ मेटेरियल मलेशिया (\*\*\*) मी.टन) और मेसर्ज त्रिवेणी स्पनिंग मिल, नेपाल (\*\*\*) मी.टन), मेसर्ज रिलायन्स स्पनिंग मिल्स लिमिटेड, नेपाल (\*\*\*) मी.टन) और मेसर्ज किसमेन एमसी ग्रुप (हांगकांग) कार्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग (\*\*\*) मी.टन) नामक उससे गैर-संबंधित निर्यातक/व्यापारिक कंपनियों द्वारा किए गए हैं। केवल मेसर्ज त्रिवेणी स्पनिंग मिल, नेपाल (\*\*\*) मी.टन) और मेसर्ज रिलायन्स स्पनिंग मिल्स लिमिटेड, नेपाल (\*\*\*) मी.टन) ने प्राधिकारी को अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

50. प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर की जांच की है और यह नोट किया है कि भारत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अधिकतर निर्यातों के लिए उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसी मात्रा को स्वीकार किया है, जिसके लिए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात ब्यौरों पर विचार किया गया है। निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, विदेशी भाड़े, बैंक प्रभारों, क्रेडिट के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

संरचित सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
***	***

### **मेसर्ज फ्युजियान झेंगक्वई हाई-टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड**

51. मेसर्ज फ्युजियान झेंगक्वई हाई-टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज फ्युजियान झेंगक्वई हाई-टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं, जिनमें से \*\*\*मी.टन सीधे और \*\*\*मी.टन निर्यात, मेसर्ज टिओनेल प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा किए गए हैं, जिसने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

52. प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर की जांच की है और यह नोट किया है कि भारत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अधिकतर निर्यातों के लिए उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसी मात्रा को स्वीकार किया है, जिसके लिए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात व्यौरों पर विचार किया गया है। निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, विदेशी भाड़े, बैंक प्रभारों, क्रेडिट के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

संरचित सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
***	***

### **मेसर्ज जिआंगिन हल्लुन केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य**

53. मेसर्ज जिआंगिन हल्लुन केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज जिआंगिन हल्लुन केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं, जिनमें से \*\*\*मी.टन सीधे और \*\*\*मी.टन निर्यात, उसने गैर-संबंधित पक्षकारों द्वारा किए हैं, जिसने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

54. प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर की जांच की है और यह नोट किया है कि भारत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अधिकतर निर्यातों के लिए उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसी मात्रा को स्वीकार किया है, जिसके लिए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत निर्यात व्यौरों पर विचार किया गया है। निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, विदेशी भाड़े, बैंक प्रभारों, क्रेडिट के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन करने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत निम्नानुसार है:-

संरचित सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
***	***

### **मेसर्ज फ्युजियान झिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड**

55. मेसर्ज फ्युजियान झिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज फ्युजियान झिंगवेई न्यू फाईबर साईस एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन निर्यात, मेसर्ज एमजीएसजीसी एंड एसएलएलसी डीबीए सेवन हिल्स इम्पोर्ट्स, यूएसए नामक गैर-संबंधित निर्यातक के माध्यम से किए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि इस निर्यातक/व्यापारी ने प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस निर्यातक और व्यापारी द्वारा पूरे उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्राधिकारी, विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए उसके उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

### **मेसर्ज किसानिन् विंसागलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड**

56. मेसर्ज किसानिन् विंसागलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, जिसमें उसने स्वयं को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज किसानिन् विंसागलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट-2 से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के कुल \*\*\* मी.टन निर्यात किए हैं। जिसमें से उसके द्वारा 2 % निर्यात सीधे और बाकी 98 % निर्यात गैर-संबंधित व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं, जिन्होंने प्राधिकारी को अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे निर्यातक और व्यापारी द्वारा पूरे उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्राधिकारी, विशिष्ट पृथक पाटन और क्षति मार्जिन स्वीकृत करने के लिए उसके उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

## **II. इंडोनेशिया**

### **मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य**

57. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है। ये पूरे और ठीक ढंग से हैं। उत्पादक की सत्यापित सूचना के आधार पर उत्पादन की लागत का निर्धारण किया गया था और घरेलू बिक्री कारोबार की जांच की गई थी तथा यह पाया गया था कि घरेलू बिक्रियां व्यापारिक कारोबार के दौरान हुई हैं। इसलिए प्राधिकारी ने संपूर्ण घरेलू बिक्रियों के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई की है। उत्पादक ने परिवहन, क्रेडिट लागत और बीमा के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे दिया गया है।

### **मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया के मामले में निर्यात कीमत**

58. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशिया ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के सीधे निर्यात किए हैं। निर्यातक ने कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निबल निर्यात कीमत नीचे दी गई है।

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
मेसर्ज पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके	***	***

## **III. थाईलैंड**

### **मेसर्ज इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पीसीएल, थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

59. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है। ये पूरे और ठीक ढंग से हैं। उत्पादक की सत्यापित सूचना के आधार पर उत्पादन की लागत का निर्धारण किया गया था और घरेलू बिक्री कारोबार की जांच की गई थी तथा यह पाया गया था कि घरेलू बिक्रियां व्यापारिक कारोबार के दौरान हुई हैं। इसलिए प्राधिकारी ने संपूर्ण घरेलू बिक्रियों के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई की है।

उत्पादक ने परिवहन, क्रेडिट लागत और बीमा के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे दिया गया है।

#### **मेसर्ज इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पीसीएल, थाईलैंड के मामले में निर्यात कीमत**

60. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पीसीएल, थाईलैंड ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के सीधे निर्यात किए हैं। निर्यातक ने कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। सामान्य मूल्य और निबल निर्यात कीमत का परिकलन औसत आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
मेसर्ज इंडोरामा पालिएस्टर इंडस्ट्रीज पीसीएल	***	***

#### **IV. मलेशिया**

#### **मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

61. मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उसकी जांच की गई थी और यह पाया गया है कि उसने मलेशिया में संबद्ध वस्तुएं नहीं बेची हैं, जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-1 से भी स्पष्ट पता चलता है। इसलिए विधिवत् सत्यापन के बाद निर्यातकों के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया है।

#### **मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी के मामले में निर्यात कीमत**

62. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने सीधे भारत को संबद्ध वस्तुएं समुद्री जहाज से भेजी हैं। निर्यात के सभी सहायक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए गए थे। निर्यातक ने कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बैंक प्रभारों, क्रेडिट लागत, अन्य व्यय और निर्यात प्रोत्साहन के लिए समायोजन करने का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। सामान्य मूल्य और निबल निर्यात कीमत का परिकलन औसत आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी	***	***

#### **पाटन मार्जिन**

63. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना-गत स्तर पर वास्तविक सामान्य मूल्य (जहां कहीं भी वास्तविक सामान्य मूल्य उपलब्ध/स्वीकार्य नहीं हुआ है, वहां उसे संरचित किया गया है) और निबल निर्यात कीमत के साथ तुलना करके की गई है।

क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	एनवी/सीएनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
			अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	%	सीमा
1.	मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन	1. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड  2. मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***	15- 25
2.	मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज जिआंगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15- 25
3.	मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोलिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम)	1. मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोलिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम)  2. मेसर्ज क्सामिन क्सिंगलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड  3. मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***	20- 30
4.	मेसर्ज फ्युजियान झेंक्वी हाई टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज फ्युजियान झेंक्वी हाई टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20- 30

इंडोनेशिया							
5.	पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशियां	पीटी इंडो-रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशियां	***	***	***	***	15- 25
थाईलैंड							
6.	इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	***	***	***	***	01- 10
मलेशिया							
7.	मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी	***	***	***	***	15- 25

64. यह देखा गया है कि सभी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

**ख. क्षति का मूल्यांकन और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए कार्य-प्रणाली**

**घरेलू उद्योग के विचार**

65. वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान क्षति के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) अनेक वर्षों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने वृद्धि दर्शाई है और जांच अवधि में उनमें अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (2) मांग में संबद्ध देशों के बाजार का हिस्सा अत्यधिक है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। इसका कारण संबद्ध देशों से अत्यधिक आयात होना है।
- (3) घरेलू उद्योग की कीमतें, घरेलू बाजार में आयातकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती हैं।
- (4) कम कीमत पर बिक्री और कीमतों में कटौती सकारात्मक और अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास होने के कारण नुकसान हो रहा है क्योंकि वह अपनी कीमतों को उचित रूप से वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण संबद्ध देशों से पाटित और क्षति कीमतों पर अत्यधिक मात्रा में आयातों का होना है।
- (5) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ के रूप में तेजी से बहुत अधिक गिरावट आई है।

- (6) संबद्ध देशों से अलाभप्रद कीमतों पर आयात की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- (7) बिक्री कीमत में गिरावट, उत्पादन की लागत में गिरावट से बहुत अधिक थी और इस प्रकार पाटित आयात, घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास होने के प्रभाव डाल रहे हैं।
- (8) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान दशा निरंतर जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने का खतरा है।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

66. वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान क्षति के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और समस्त क्षति जांच अवधि के दौरान उसमें सुधार हुआ है।
- (2) याचिकादाताओं द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से पता चलता है कि वह कथित रूप से पाटित आयातों के कारण किसी प्रकार की क्षति को दर्शाने में विफल रहे हैं।
- (3) याचिकादाताओं ने वर्तमान मामले में क्षति के संचयी मूल्यांकन की विधि को अपनाया है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित है।
- (4) एडीए के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत क्षति विश्लेषण में जांच प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक साक्ष्य और वास्तविक जांच के लिए संबंधित तीन कारकों की जांच करने की आवश्यकता है, प्रथमतः पाटित आयातों की मात्रा, द्वितीयक समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और तृतीयक समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच करना, जांच प्राधिकारी का दायित्व है।
- (5) याचिकादाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, अनुच्छेद 3.2 के अंतर्गत समग्र रूप से अथवा सापेक्षिक रूप से आयातों में “अत्यधिक” वृद्धि होने का समर्थन नहीं करता है।
- (6) संबद्ध देशों से आयातों से भिन्न अन्य कारक, घरेलू उद्योग को हुई किसी भी प्रकार की कथित क्षति के कारण हो सकते हैं।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

67. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (3) और (4) के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की जानी अपेक्षित है।

68. प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण में वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए विभिन्न निवेदनों का निदान किया गया है।

69. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 और डीजीएडी की सुस्थापित पद्धति के अनुसार क्षति रहित कीमत परिकलित की है।

70. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर विचार किया है।

## I. मांग का मूल्यांकन

71. इस प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को समग्र भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योगफल के रूप में लिया है। चूंकि जांच अवधि 18 महीनों (अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016 तक) की है, इसलिए पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रभावी तुलना करने के लिए जांच अवधि के आंकड़ों को संक्षिप्त बनाया गया है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	8,411	24,876	44,409	75,279	50,186
अन्य देशों से आयात	मी.टन	2,584	3,780	4,224	8,901	5,934
कुल आयात	मी.टन	10,995	28,656	48,633	84,181	56,120
आवेदनकर्ताओं की घरेलू बिक्रियां -	मी.टन	228,540	248,652	270,509	440,012	293,341
अन्य की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	486,050	462,500	447,400	685,050	456,700
कुल घरेलू बिक्रियां	मी.टन	714,590	711,152	717,909	1,125,062	750,041
कुल मांग (मी.टन)	मी.टन	725,585	739,808	766,542	1,209,242	806,161
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	106	167	111

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में और समग्र क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल मांग में वृद्धि हुई है।

## II. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

### आयात की मात्रा और आयातों में बाजार का हिस्सा

73. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। चूंकि जांच अवधि 18 महीनों (अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016 तक) की है, इसलिए पूर्ववर्ती अवधि के साथ प्रभावी तुलना करने के लिए जांच अवधि के आंकड़ों को वार्षिकीकृत बनाया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि (अप्रैल 2015- सितंबर 2016)	जांच अवधि -वार्षिकीकृत
चीन से आयात	मी.टन	6,261	20,632	33,956	52,261	34,841
इंडोनेशिया से आयात	मी.टन	0	135	4,344	10,900	7,267
मलेशिया से आयात	मी.टन	2,046	1,999	2,204	5,251	3,501
थाईलैंड से आयात	मी.टन	104	2,111	3,904	6,867	4,578



संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	8,411	24,876	44,409	75,279	50,186
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	296	528	895	597
अन्य देशों से आयात	मी.टन	2,584	3,780	4,224	8,901	5,934
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	163	344	230
कुल आयात	मी.टन	10,995	28,656	48,633	84,181	56,120
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	261	442	766	510
<b>कुल आयातों में हिस्सा</b>						
संबद्ध देशों का	%	76	87	91	89	76
अन्य देशों का	%	24	13	9	11	24

74. कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा लगभग 89% है। शेष 11% आयात, दक्षिण कोरिया और ताईवान से हुए हैं, जब कि अन्य देशों का हिस्सा तुच्छ है। कोरिया और ताईवान से आयात अधिक कीमतों पर हुए हैं, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है। उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि विगत वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में समग्र रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

### III. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

75. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में आरोपित पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक ह्रास करते या कीमतों में वृद्धि को रोकते, जो कि अन्यथा अत्यधिक मात्रा में हो गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनिकरण, यदि कोई हुआ है, के संदर्भ में की गई है।

#### (क) कीमत में कटौती

76. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, आयातों की पहुंच कीमत (डीजीसीआईएंडएस के अनुसार) की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	कुल
संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/मी.टन	71,856
निबल बिक्री कीमत	रूपए/मी.टन	***
कीमत में कटौती	रूपए/मी.टन	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)
कीमत में कटौती	सीमा	(5)-5

77. विश्लेषण से पता चलता है कि सभी संबद्ध देशों से (संचयी रूप से) आयातों का पहुंच मूल्य, भारत में घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत से अधिक है और इसलिए कीमत में कटौती नकरात्मक है।

**(ख) कम कीमत पर बिक्री**

78. घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की जांच, आयातों की पहुंच कीमत की तुलना क्षति रहित कीमत के साथ करके की गई है।

विवरण	यूनिट	कुल
संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/मी.टन	71,856
क्षति रहित कीमत	रूपए/मी.टन	***
कीमत में कटौती	रूपए/मी.टन	***
कीमत में कटौती	%	***
कीमत में कटौती	सीमा	1-10

79. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत, क्षति रहित कीमत से कम है और इसलिए कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

**(ग) कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण**

80. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अत्यधिक स्तर पर कीमत ह्रास हुआ है और कीमत में वृद्धि करने में रूकावट आई है, जो कि सामान्य स्थिति में अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती, याचिकादाता ने बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमतों के आंकड़े दिए हैं और क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तन पर विचार किया गया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि -वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों के आयातों का पहुंच मूल्य	रूपए/ मी.टन	93,138	98,959	88,634	71,856
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	106	95	77
बिक्रियों की लागत	रूपए/ मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	92	78
घरेलू बिक्री कीमत	रूपए/ मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	94	79

81. यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 में हुई वृद्धि को छोड़ कर समस्त क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि और समस्त क्षति अवधि के

दौरान बिक्री कीमत, बिक्रियों की लागत से कम है। आयातों का पहुंच मूल्य (डीजीसीआईएंडएस के अनुसार) बिक्रियों की लागत से कम है और घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत को आयातों के पहुंच मूल्य से कम रखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में हास और न्यूनीकरण हुआ है। तथापि, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अन्य उत्पादकों के पास बाजार का प्रमुख हिस्सा है, जो कि प्रचलित बाजार कीमतें तय करता है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित होती हैं।

#### IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

82. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II में उल्लिखित प्रावधान में क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्य परक जांच करना निहित है। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का तथ्य परक और निष्पक्ष जांच करना शामिल है, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता भी शामिल है।

83. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।

#### (क) बाजार का हिस्सा

84. आयातों, घरेलू बिक्रियों और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से की व्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि -वार्षिकीकृत
1	कुल घरेलू बिक्रियां	मी.टन	714,590	711,152	717,909	750,041
1 (क)	घरेलू बिक्रियां - आवेदक	मी.टन	228,540	248,652	270,509	293,341
1 (ख)	घरेलू बिक्रियां - अन्य	मी.टन	486,050	462,500	447,400	456,700
1 (ग)	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	105
2	संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	8,411	24,876	44,409	50,186
3	अन्य देशों से आयात	मी.टन	2,584	3,780	4,224	5,934
4	कुल आयात	मी.टन	10,995	28,656	48,633	56,120
5	कुल मांग	मी.टन	725,585	739,808	766,542	806,161
5 (क)	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	102	106	111
6	मांग में बाजार का हिस्सा					
6 (क)	कुल घरेलू बिक्रियों में से	%	98.48	96.13	93.66	93.04
6 (ख)	घरेलू उद्योग की बिक्रियों में से		31.49	33.61	35.28	36.38
6 (ग)	संबद्ध देशों के आयातों में से	%	1.16	3.36	5.79	6.23
6 (घ)	अन्य देशों के आयातों में से	%	0.36	0.51	0.55	0.74

85. आधार वर्ष से जांच अवधि तक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में समग्र रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में कुल मांग ने सुसंगत वृद्धि दर्शाई है, लेकिन पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान कुल मांग में (सभी उत्पादकों की) घरेलू बिक्रियों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जबकि उसी अवधि के दौरान याचिकादाताओं और संबद्ध देशों से आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

**(ख) लाभप्रदता**

86. घरेलू उद्योग ने बताया है कि जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमतों की तरह बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि बिक्री कीमतों में पर्याप्त गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से निरंतर कम बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप समग्र क्षति अवधि के दौरान उसे निरंतर घाटे हुए हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि उन्हें पहुंच पश्चात निर्यातकों द्वारा पेश की जा रही घटी कीमतों के बराबर अपनी कीमतों को बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ा है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि -वार्षिकीकृत
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	92	78
बिक्री कीमत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	94	79
लाभ/हानि	रूपए/मी.टन	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(124)	(68)	(71)
लाभ/हानि	लाख रूपए	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(135)	(81)	(136)

87. आंकड़ों से पता चलता है कि समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर घाटे हो रहे हैं। तथापि, भारत में अन्य उत्पादक बाजार के पर्याप्त हिस्से पर नियंत्रण रखे हुए हैं और देश में आयातों के साथ कीमत ढांचे पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए।

**(ग) निवेश पर प्रतिलाभ**

88. निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक नकारात्मक रहा है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
निवेश पर प्रतिलाभ	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(265)	(190)	(319)

89. घरेलू उद्योग ने निवेश पर प्रतिलाभ के निरंतर नकारात्मक होने के बावजूद भी समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता और उत्पादन में निरंतर वृद्धि की है। इसलिए निवेश पर नकारात्मक प्रतिलाभ, घरेलू उद्योग की क्षति का निर्णायक सूचक नहीं है।

#### (घ) उत्पादन और क्षमता उपयोग

90. यह बताया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यतया इस तथ्य के कारण है कि मांग में भी वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि देश में मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का प्रचालन कर रहा है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	441,102	497,862	504,450	505,110
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	114	115
कुल उत्पादन	मी.टन	308,207	322,487	337,117	350,108
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	109	114
क्षमता उपयोग	%	69.87	64.77	66.83	69.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	96	99

91. आधार वर्ष और विगत वर्षों की तुलना में समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है। समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जो कि मांग में वृद्धि होने के कारण हो सकी है।

#### (ङ) बिक्रियों की मात्रा

92. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष और विगत वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यतया इस तथ्य के कारण है कि मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात कम हुए हैं। तथापि, वर्तमान विश्लेषण में केवल घरेलू बिक्रियों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। इसलिए विश्लेषण निर्यातों द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
घरेलू	मी.टन	228,540	248,652	270,509	293,341
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	128
निर्यात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	91	76

**(च) मालसूचियां**

93. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	89	56

94. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग की बेहतर बाजार स्थिति का पता चलता है।

**(छ) उत्पादकता, रोजगार और वेतन**

95. यह बताया गया है कि उत्पादन में वृद्धि होने के जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसका कारण यह है कि उसे पाटित आयातों द्वारा पेश की जा रही कीमतों के बराबर लागतों में कटौती करनी पड़ी है। तथापि, जांच अवधि के दौरान उनको अदा किए गए वेतन में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि - वार्षिकीकृत
उत्पादन (मी.टन)	मी.टन	308,207	322,487	337,117	350,108
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	98	62
उत्पादन/कर्मचारी	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	112	123
वेतन/कर्मचारी	रूपए/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	117	190

96. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि से बेहतर कार्य-कुशलता का पता चलता है और वेतन में वृद्धि, समय के साथ सामान्य बाजार दशाओं की प्रगतिशील स्थिति के कारण हो सकती है।

**(ज) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन**

97. पाटन की मात्रा इसका संकेतक है कि किस सीमा तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।

**(झ) संवृद्धि**

98. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन और बिक्रियों के रूप में घरेलू उद्योग की सकारात्मक संवृद्धि थी। तथापि, पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि में मांग में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद लाभ और नकदी लाभ के साथ-साथ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नकारात्मक बना हुआ है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि होने के साथ घरेलू उद्योग ने लाभ, सुगम नकदी प्रवाह और निवेशों पर प्रतिलाभ में वृद्धि होने की आशा की थी। तथापि, घरेलू उद्योग अलाभप्रद कीमतों पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के विद्यमान रहने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर सका है।

**(ञ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

99. जांच से पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी मांग थी। हालांकि घरेलू उद्योग के पास बाजार का प्रमुख हिस्सा है, उसका दावा है कि आयात की कीमतें, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। तथापि, तथ्य यह है कि अन्य भारतीय उत्पादक भी जिनके पास बाजार का प्रमुख हिस्सा है, संबद्ध वस्तुओं की बाजार कीमतों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण किया है, जिसके कारण उसे वित्तीय घाटे हुए हैं। संबद्ध देशों से भिन्न अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा में कम हैं और उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है क्योंकि इन देशों द्वारा पेश की जा रही कीमतें बहुत अधिक हैं। उत्पाद की मांग वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रही है और इसलिए यह कारक घरेलू उद्योग के सामने पेश आ रहे कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आरोपित पाटित आयात और अन्य उत्पादक घरेलू उद्योग के कीमत ढांचे में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

**ज. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध**

100. वास्तविक क्षति, मात्रा और कम कीमत पर बिक्री करने और कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के रूप में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव तथा अवनति के प्रभाव, नियमावली और पाटन-रोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सूचक प्राचलों की जांच करने पर प्राधिकारी ने यह देखने की कार्रवाई की है कि क्या पाटित आयातों से भिन्न अन्य कोई कारक घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

**(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

101. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भिन्न अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात मात्रा में अत्यधिक नहीं हैं और वे अधिक कीमतों पर हुए सूचित किए गए हैं। इसलिए अन्य देशों से आयातों को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

**(ख) मांग में संकुचन**

102. समस्त क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में गिरावट, घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

**(ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

103. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

**(घ) प्रतिस्पर्धा की दशाएं और व्यापार की प्रतिबंधित पद्धतियां**

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

**(ङ) प्रौद्योगिकी में विकास**

105. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारक नहीं है।

**(च) निर्यात निष्पादन**

106. प्राधिकारी द्वारा केवल उनके घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रख कर क्षति विश्लेषण किया गया है। इसलिए निर्यात बाजार में निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

**(छ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन**

107. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति का विश्लेषण, केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कार्य-निष्पादन ने वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया है।

**(ह) भारत में अन्य प्रोड्यूसर्स**

108. भारत में विषय वस्तुओं का एक और बड़ा उत्पादक है, जो इस याचिका में शामिल नहीं हुआ है, हालांकि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूत बताता है कि यह विषय वस्तु के बाजार मूल्यों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**(झ) क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

109. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति-रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार से आकलित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	एनवी/सीएनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
			अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	%	सीमा
चीन जनवादी गणराज्य							
1.	मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन	1. मेसर्ज जिआंगिन हुआहोंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड  2. मेसर्ज यूनाईटेड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***	5-15



3.	मेसर्ज जिआगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज जिआगिन हेलुम केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15
4.	मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोलिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम),	1. मेसर्ज फ्युजियान जिनलुम फाईबर शेयरहोलिंग कंपनी लिमिटेड (जिनलुम) 2. मेसर्ज क्सामिन क्सिगलु केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड 3. मेसर्ज यूनाईटेड राँ मेटेरियल पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
7.	मेसर्ज फ्युजियान झेंक्वी हाई टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज फ्युजियान झेंक्वी हाई टेक फाईबर टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
इंडोनेशिया							
8.	पीटी इंडो- रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशियां	पीटी इंडो- रामा सिंथेटिक्स टीबीके, इंडोनेशियां	***	***	***	***	1-10
थाईलैंड							
9.	इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	इंडोरामा पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	***	***	(***)	(***)	(5)-5

मलेशिया							
10.	मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज रेकरोन मलेशिया एसडीएन बीएचडी	***	***	***	***	5-15

### **झ प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**

110. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें उठाए गए मुद्दे जांच के दौरान पहले ही उठाए जा चुके हैं और उपयुक्त ढंग से उनका समाधान भी कर दिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की जा रही है:-

### **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

111. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. मांग के साथ-साथ बाजार हिस्से की न केवल घरेलू उद्योग के लिए अपितु संपूर्ण बाजार के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि क्षति के कारक के रूप में बाजार हिस्सा भी घरेलू उद्योग के लिए क्षति दर्शा रहा है क्योंकि सभी घरेलू उत्पादकों के हिस्से में गिरावट आई है।
- ख. घरेलू बाजार में पीएसएफ की कीमतें आयात समानता आधार पर निर्धारित की जाती है। बाजार अन्तरराष्ट्रीय रूप से अत्यंत प्रतिस्पर्धी है और भारत में किसी भी उत्पादक, लघु अथवा प्रमुख के लिए अंतराष्ट्रीय कीमतों जिन पर भारत में वस्तुओं का आयात किया जा सकता है, को ध्यान में रखे बिना अपनी कीमतें निर्धारित करना संभव नहीं है। कीमत निर्धारण डायनामिक्स याचिकाकर्ता कम्पनियों के साथ-साथ असहयोगी याचिकाकर्ता कम्पनियों के लिए वही बने रहे क्योंकि वे एकदम उन्हीं स्थितियों में उसी बाजार में अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रहा है और उनकी क्षति का कारण बन रहा है और असहयोगी उत्पादक के लिए भी वहीं तंत्र है।
- ग. आयात कुल मांग का केवल लगभग 7 प्रतिशत है, इसलिए इस तथ्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि घरेलू बाजार में कीमतें आयात कीमतों के आधार पर निर्धारित की जा रही हैं। देश में घरेलू उत्पादन के संदर्भ में आयात 14 प्रतिशत से अधिक है जोकि बाजार में कीमतों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है।
- घ. निवेश की ऋणात्मक दर कम कीमत प्राप्ति का एक कार्य है और इसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं है कि संस्थापित क्षमता और उत्पादन बढ़ गया है।
- ङ. मालसूची और प्रति व्यक्ति वेतन के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि पीओआई के आंकड़े वार्षिकीकृत नहीं किए गए हैं और जिन्हें कृपया सही किया जाए।

### **विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध**

112. विभिन्न विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सार नीचे दिया गया है:-

- क. प्राधिकारी स्पष्टतः यह स्पष्ट करे कि "रिसाइक्लड पीएसएफ, नॉन डाइड अथवा कलर्ड को पीयूसी के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है। इसे भी शुल्क तालिका नोट का एक भाग बनाया जाए ताकि यदि इस मामले में प्राधिकारी किसी शुल्क की सिफारिश करते हैं तो सामग्री की अनुमति के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी किसी संदेह से बच सकें।

- ख. मैसर्स पीटी इंडोरामा पेट्रोकेमिकल्स, इंडोनेशिया कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषितानुसार साझा नियंत्रण होने के कारण आवेदक से संबद्ध है जो वर्ष 2016-17 के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट से सिद्ध होता है। इसलिए प्राधिकारी के लिए लोहिया परिवार सदस्यों जो भारत में इंडोरामा ग्रुप और संबद्ध देशों के लाभार्थी स्वामी है, के बीच कारपोरेट क्रॉस स्वामित्व को प्रकट करना अनिवार्य है।
- ग. आरआईएल को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं मानने से निश्चित रूप से क्षति को बढ़ाने में काफी जोखिम पूर्ण होगा। यह भारत में पीयूसी का प्रमुख उत्पादक है और आरआईएल का फोकस पीयूसी के उत्पादन पर बना रहा है और इसने अपना फोकस आयातित पीयूसी में व्यापार पर परिवर्तित नहीं किया है। पीओआई के दौरान रिक्रोन द्वारा निर्यातित पीयूसी की अल्प मात्रा मिलों द्वारा निजी खपत के लिए प्रयोग की गई है। आरआईएल यह नहीं कह सकता कि अवांछित रूप से लाभांशित हुआ है और इसलिए इसको बाहर करने की पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1(i) की शर्तों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए थी।
- घ. प्राधिकारी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 20 नवम्बर, 2017 के आदेश के तहत किए गए निर्णयों का अनुपालन करने में विफल रहे हैं क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए कोई जांच/विश्लेषण नहीं किया गया है कि रिक्रोन के साथ आरआईएल के संबंध का प्रभाव ऐसा है कि जो असंबद्ध उत्पादकों से अलग तरह से व्यवहार करने के लिए उत्पादकों को क्षति का कारण हो। इसके अतिरिक्त नियमावली का नियम 2(ख)(1) अधिनियमन भाग है और एक मानद रखता है कि निर्यातक अथवा आयातक कब संबद्ध हैं। यह विश्वास करने के और भी कारण है कि पक्षकार वास्तव में कारोबार करने बच रहे थे।
- ङ. आयातों के आरोपों के लिए पर्याप्त साक्ष्य के रूप में आयात आंकड़ों की पीडीएफ/हार्ड कापी को नहीं माना जा सकता।
- च. घरेलू उद्योग ने संगतता और निष्पक्षता के सभी तर्कों और सिद्धांतों को नकारते हुए और विभिन्न आयात लेनदेनों में पूर्ण उत्पाद विवरण को छुपाते हुए पीयूसी के साथ-साथ एनपीयूसी दोनों के लिए वही अथवा उसी प्रकार के विवरण वाले आईबीआईएस आयात आंकड़ों में विभिन्न आयात लेनदेन पर विचार किया है।
- छ. मैसर्स जिंगयाइन हेलून कैमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड ने सामान्य मूल्य संरचित करने के स्थान पर उनके रिकार्ड के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। आगे यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी चीन के निर्यातकों के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए थाईलैंड की सूचना पर भी विचार करे। संरचित सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पीसीआई रिपोर्टों जिनका ब्यौरा पहले ही हमारे पूर्ववर्ती अनुरोधों के तहत उपलब्ध करा दिया गया है, में सूचित औसत मासिक कीमतों के आधार पर पीटीए और एमईजी की कच्ची सामग्री कीमतों पर विचार करने के लिए अनुरोध है। कच्ची सामग्री के लिए खपत मानदंड, अन्य लागत और लाभ चालू जांच में भागीदार थाईलैंड के उत्पादकों की सूचना के आधार पर विचार किया जाए।
- ज. मैसर्स झियामैन झियांलू कैमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से अधूरी वैल्यू चैन के आधार पर उनके प्रत्युत्तर अस्वीकार कर दिए हैं। तथापि, चीन के किसी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक ने पूरी वैल्यू चैन उपलब्ध नहीं कराई है। आगे यह भी अनुरोध है कि मैसर्स टिनोल पीटीई. लिमिटेड तथा मैसर्स झियामैन झियांलू कैमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड उक्त पाटनरोधी जांच में भाग लेने के लिए असंबद्ध व्यापारियों के लिए मजबूर कर सका अथवा अनिवार्य कर सका। प्राधिकारी निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तरों में अपने उत्तरों के आधार पर मैसर्स झियामैन झियांलू कैमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड के लिए अलग पाटन मार्जिन अनिवार्यतः निर्धारित करे। वास्तव में प्राधिकारी यूनाइटेड रॉ मैटिरियल पीटीई लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर को अनिवार्यतः अस्वीकृत करे

क्योंकि उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली के आंशिक/अपूर्ण उत्तर दिए हैं और मैसर्स झियामैन झियांलू कैमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित वस्तुओं के बीजक से संबंधित सूचना छिपाई है।

- झ. कई प्रयोक्ताओं/डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं/उद्योगों/एशोसिएशनों ने अनुरोध किया है कि मैन मेड फाइबर टेक्सटाइल के विनिर्माण में पीएसएफ की घरेलू खपत 800,000 एमटी वार्षिक है। पीएसएफ विनिर्माण उद्योग का ढांचा उन्हें यार्न स्पिनिंग मिलों की तुलना में आयात समानता कीमतों से काफी अधिक कीमतें वसूलने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कीमतें मांग और आपूर्ति के डायनामिक्स का ध्यान रखे बिना आवधिक रूप से घोषित की जाती है। यह एमएमएफ यार्न और फैब्रिक को अधिक मंहगी बनाता है जो भारत में एमएमएफ टेक्सटाइल उद्योग के विकास को रोकता है। पाटनरोधी शुल्कों द्वारा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास की लागत पर विनिर्माताओं के लिए पीएसएफ की घरेलू कीमतें आगे कोई मंहगा-समृद्ध संरक्षण करेंगी। भारत में पीएसएफ की उच्च लागत भी यार्न और फैब्रिक के आयात को प्राप्ताहित करेगी जिससे वैल्यू चेन के साथ विकास रुकेगा/बंद होगा। 8 रुपए प्रति किलोग्राम की एडीडी 640 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बनते हैं और 5 वर्ष की अवधि में 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। इस पाटनरोधी शुल्क से पीएसएफ का आयात बंद होगा और मूल्य वर्धित यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के अधिक मूल्य से प्रतिस्थापित किए जा सकेंगे।
- ञ. घरेलू उत्पादन और घरेलू खपत की तुलना में आयात के संबंध में विश्लेषण नहीं किया गया है।
- ट. घरेलू उद्योग की लागत में कमी कच्चे तेल की कीमतों पतन के कारण प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात् पीटीए और एमईजी की कीमतों में कमी के कारण है जो यह दर्शाता है कि कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि पीटीए और एमईजी की लागत पीएसएफ की लागतों का 80 प्रतिशत से अधिक है। आगे यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने लागतों में पूरी कमी को अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है जैसा कि यह क्षति जांच अवधि के दौरान 36 प्रतिशत तक घरेलू उद्योग के लिए हानियों में काफी कमी से दिखाई देता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान जांच में भी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है।
- ठ. संबद्ध आयात और घरेलू कीमतों के बीच परस्पर क्षति जांच अवधि के दौरान समानान्तर मूल्य निर्धारण का अस्तित्व मात्र कीमत के प्रभाव के अस्तित्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं बनता क्योंकि अन्य कारक भी हो सकते हैं जिन्होंने घरेलू कीमतों और आयात कीमतों दोनों को कम किया हो।
- ड. कुल घरेलू बिक्री में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बिक्री भी शामिल है जबकि भाग 2 में आवेदकों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्राधिकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाहर रखने का दावा किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पक्ष तथा बाजार हिस्से के संबंध में विरोधाभासी अनुरोध और विश्लेषण कर रहा है जिसके लिए अनुमति नहीं दी जाए।
- ढ. घरेलू उद्योग ने एक तरफ यह कहते हुए विरोधाभासी बयान दिया है कि लागतों में कमी करने और कथित आयात द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों की संख्या में कमी की है जबकि दूसरी तरफ यह कहा गया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन में 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान जांच में कर्मचारियों की संख्या की गणना ठीक प्रतीत नहीं होती क्योंकि आवेदक कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं। जिस समय 2013-14 में घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी उस समय वेतन कम था और जब पीओआई में कर्मचारियों की संख्या सबसे कम थी तब वेतन सबसे अधिक था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा ठीक नहीं है और गुमराह करने वाला है।
- ण. रिसाइकल्ड पीएसएफ उद्योग में वर्धित क्षमता ने भी पीएसएफ कारोबार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुण-धर्म साझा करते हुए रिसाइकल्ड पीएसएफ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पादों का एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी है।

- त. घरेलू उद्योग अपने इस समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि घरेलू उद्योग को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई लदान पश्चात छूट दी गई कीमतों के लिए मजबूर किया गया था।
- थ. आवेदक उत्पादकों द्वारा घरेलू बाजार में उच्च कीमते वसूलना भी एक दूसरा कारण है कि वे घरेलू बाजार में कीमतों को निर्देशित करने की स्थिति में हैं अन्यथा निर्यात बाजार में उनकी बिक्री कम नहीं हो सकती थी।
- द. घरेलू उद्योग के लिए निरन्तर हानि क्षति जांच अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यहास लागत, ब्याज लागत, मजदूरी लागत, ऊपरी खर्चों आदि में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि के कारण है।
- ध. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य घरेलू उत्पादकों की उपलब्ध कीमतों पर विचार करने के बाद संपूर्ण उद्योग के लिए आकस्मिक कारक विश्लेषण किया जाए। घरेलू उद्योग की परिभाषा से इसे बाहर कर दिया जाता है तो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आइसोलेसन की जरूरत नहीं है। घरेलू कीमतों पर आरआईएल के प्रभुत्व और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव में भेद और पृथक् किया जाना चाहिए और संबद्ध आयात के कारण हुआ नहीं माना जाना चाहिए।
- न. किसी अन्य ज्ञात कारक की क्षति का कारण नहीं होने की वजह से भी जांच की जाए और इस प्रकार की क्षति को संबद्ध आयात के कारण हुआ नहीं माना जाए।
- ण. नियोजित औसत पूंजी पर कर-पूर्व आय के रूप में 22 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित एनआईपी अत्यधिक बढ़ाई गई है और वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

113. यह नोट किया गया है कि उपरोक्त संगत पैराओं में प्राधिकरण द्वारा प्रकटन पश्चात चरण में उठाए गए मुद्दों पर पहले से ही जांच की जा चुकी है। पीयूसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और किसी भी भ्रम का कारण होने की संभावना नहीं है। वर्तमान जांच में शामिल इच्छुक पक्षों के बीच डीआई खड़े और संबंध के मुद्दे पर चर्चा की गई है और सभी संबंधित मुद्दों को पूर्ववर्ती प्रासंगिक पैराग्राफ में संबोधित किया गया है। पीयूसी के लिए उत्पादन की लागत और निधि का निर्धारण नियमों और निदेशालय में किए गए प्रथाओं के अनुसार किया गया है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से सहकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर आयात मात्रा और मूल्य के अन्य मापदंडों की जांच की गई है। जैसा कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जैसा कि ऊपर पैरा में बताया गया है। मैसर्स ज़ियामेन जियानग्लू केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड को पूरी जानकारी के अभाव के मद्देनजर व्यक्तिगत डंपिंग और चोट मार्जिन प्रदान नहीं किया गया है। विभिन्न संबंधित कारकों और गैर-एट्रिव्यूशन विश्लेषण का प्रभाव विश्लेषण भी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है। उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा याचिकाकर्ता कंपनियों की तुलनात्मक कीमतों, गैर-याचिकाकर्ता (भारतीय) कंपनी और विषय देशों से विषय वस्तु के आयात की कीमतों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियां भी जांच की गई हैं और उनका उचित विश्लेषण किया गया है।

### **श. निष्कर्ष**

114. उठाए गए मुद्दों और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और इस निष्कर्ष में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निर्णय करते हैं:-

- i. मूल वर्ष की तुलना में पीआईआई के दौरान पीयूआई के आयात में वृद्धि हुई है, हालांकि, भारत में कुल मांग की तुलना में यह मात्रा पर्याप्त नहीं है। आयात की हिस्सेदारी केवल 7% है जो डीआई द्वारा भौतिक चोट के कारण पर्याप्त नहीं है।

- ii विचाराधीन उत्पाद भारत को सभी विषय देशों से निर्यात किया गया है, जो कि संबंधित विषयों के देशों में सामान्य मूल्य के मुकाबले पड़े हुए कीमतों पर निर्यात किया जाता है, हालांकि, यह केवल घरेलू उद्योग में भौतिक चोट के कारण जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि विश्लेषण विभिन्न आर्थिक मापदंडों का
- iii चोट विश्लेषण इंगित करता है कि घरेलू उद्योग में कुछ आर्थिक विकास मापदंडों पर पीड़ित है, हालांकि, यह अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है जो मौजूदा एंटीडिंग जांच के दायरे से परे हैं।
- iv भारत में अन्य उत्पादक, जो इस याचिका में शामिल नहीं हुए हैं, मांग का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और विषय वस्तु की प्रचलित कीमतों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है जैसा कि उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा दर्ज विभिन्न सबमिशन की परीक्षा से स्पष्ट है।
- v वर्तमान मामलों में उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों की विस्तृत परीक्षा डंपिंग का निर्णायक सबूत नहीं है, यह घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता, उत्पादन, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी आदि में सकारात्मक वृद्धि से स्पष्ट है।

#### डॉ. सिफारिश

115. प्राधिकरण में कहा गया है कि जांच शुरू की गई और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया और डंपिंग, चोट और साझे लिंक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी देने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पर्याप्त अवसर दिया गया। एडी नियमों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और उसके कारणों की जांच शुरू करने और आयोजित करने के बाद यह स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया जाता है कि कथित आयात घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति के कारण निर्णायक रूप से केवल जिम्मेदार नहीं हैं। प्राधिकरण का मानना है कि मौजूदा जांच में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण नियमों के नियम 14 (बी) के अनुसार जांच की समाप्ति की सिफारिश करने के लिए उचित मानता है।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

#### (FINAL FINDINGS)

**Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.**

**F. No. 14/49/2016-DGAD.**—1. Whereas, M/s. Alok Industries Ltd., M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd. and M/s The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd., (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers (excluding recycled PSF and

specialty fibers namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres)” from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 14/49/2016-DGAD dated 2<sup>nd</sup> February 2017, published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter also referred to as the Subject Countries) and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

#### **A. PROCEDURE**

3. The procedure described here under has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The Authority notified the Embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
  - ii. The Authority issued a notification dated 2<sup>nd</sup> February, 2017, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
  - iii. The Embassy of the subject countries in India was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within prescribed time limit.
  - iv. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - i. M/s. Cixi Jiangnan Chemical Co. Ltd., China
    - ii. M/s. Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd., China
    - iii. M/s. Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd., China
    - iv. M/s. P.T. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk, (TIFICO), Indonesia
    - v. M/s. P.T. Indorama Synthetics Tbk, Indonesia
    - vi. M/s. P.T. Sulindafin, Indonesia
    - vii. M/s. P.T. Branta Mulia Tbk, Indonesia
    - viii. M/s. P.T. Indonesia, Toray Synthetics, Indonesia
    - ix. M/s. Pen Fibre Sdn Bhd, Malaysia
    - x. M/s. Recron (Malaysia) Sdn Bhd., Malaysia
    - xi. M/s. Kangwal Polyester, Indonesia
  - v. In response to the above notification, following exporters/producers have submitted exporter questionnaire responses.
    - i. M/s. Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd.China
    - ii. M/s. Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China
    - iii. M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd., China
    - iv. M/s. Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co. Ltd., China
    - v. M/s. Xiamin MC Group (Hk) Corp. Ltd., China
    - vi. M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. (Jinlun), China
    - vii. M/s. Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd., China
    - viii. M/s. United Raw Material PTE Ltd., China

- ix. M/s. PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia
- x. M/s. Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand
- xi. M/s. Recron (Malaysia) Sdn Bhd., Malaysia
- vi. A Supplementary questionnaire on Market Economy conditions was also sent to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with a request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit.
- vii. Following responding producers/exporters from China have claimed MET:
  - i. M/s Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd. China
  - ii. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China
  - iii. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd., China
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. Arvind Limited
  - ii. Gulab Fibres
  - iii. Lambodhara Textiles Ltd.
  - iv. Madura Coats Private Limited
  - v. Rswm Limited
  - vi. Sree Ayyanar Spinning And Weaving Mills Ltd.
  - vii. Vardhman Textiles Ltd.
  - viii. Vardhman Yarns And Threads Limited
  - ix. Wearit Global Limited
- ix. The following importers/users have submitted importers questionnaire responses:
  - i. M/s Banswara Syntex Limited
  - ii. M/s Madura India Private Limited
  - iii. M/s Arvind Limited
  - iv. M/s Vardhman Yarns & Threads
  - v. M/s Shree Shyam Distributors
  - vi. M/s Lakshmi Mills Company Limited
  - vii. M/s Welspun India Limited
  - viii. M/s Shree Rajasthan Syntex Limited
  - ix. M/s RSWM Limited
  - x. M/s Lambodhara Textiles Limited
  - xi. M/s Sutlej textiles & industries Ltd.
  - xii. M/s PKPN Spinning Mills P. Ltd.
  - xiii. M/s Centwin Textile Mills (P) Ltd.
- x. The following parties have also made legal submissions against the petition and initiation of investigation.
  - i. M/s Vardhaman Yarns and Threads Limited
  - ii. M/s Arvind Limited
  - iii. M/s Madura Coats Private Limited



- iv. M/s Longwaliya Yarns Ltd. Ludhiana
  - v. M/s Vishnu Lakshmi Mills Ltd
  - vi. M/s Suryalata Spinning Mills Association
  - vii. M/s Rugmini Ram Raghav Spinners Ltd
  - viii. M/s Indian Texpreneurs federation
  - ix. M/s The South India Spinners Association
  - x. M/s Southern India Mills Association
  - xi. M/s Suryavanshi Spinning Mills Ltd
  - xii. M/s Sri Kannapiran Mills Ltd
  - xiii. M/s Suryalakshmi Cotton Mills Ltd
- xi. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
  - xii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
  - xiii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
  - xiv. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;
  - xv. The petition was filed on the basis of secondary source import data (IBIS data), the Authority had examined the same and found sufficient evidence for dumping and injury for initiation of investigation. The IBIS data was kept in the public file as a part of the petition. During the course of investigation, the Authority sought transaction by transaction import data for the injury period and POI from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems). The Authority has relied upon import data procured from DGCI&S for analysis of various parameters in the present investigation.
  - xvi. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 30<sup>th</sup> September, 2016 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the Period of Investigation (POI).
  - xvii. The Authority held oral hearing in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules on 23.11.2017, providing opportunity to the interested parties to present their views orally. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of their views expressed orally by 30.11.2017, followed by rejoinder submissions by 7.12.2017.
  - xviii. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Findings. The submissions filed by Embassy of subject countries/Associations/Federations/Foundations has been duly considered and addressed appropriately.
  - xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the

investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the 'facts available'

- xx. A Disclosure Statement was issued on 10.1.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 17.1.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. \*\*\* in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate for the present investigation is 1 US \$ = Rs. 66.53

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **Views of the Domestic industry**

- 4. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to product under consideration:
  - i. The product under consideration in the present application is "Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers (excluding recycled PSF and specialty fibres namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres)".
  - ii. The subject goods are predominantly used to spin yarn of 100% PSF or in blends with natural, artificial and/or synthetic staple fibres for manufacture of textiles, sewing thread, other industrial textiles and for non-woven applications, etc.
  - iii. Technical specifications of the subject PSF are defined in terms of their deniers, strength, lustres like semi dull, bright, semi bright, full dull etc., colour, cross section and cut length or staple length.
  - iv. According to the Domestic Industry, there is no difference in the subject goods produced by them and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.
  - v. The subject products are classified under HS Code 5503 20 00, however, the goods are also imported under various other HS Codes. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
  - vi. The petitioner companies have indicated the dumping margin as well as price related analysis (like price undercutting and price underselling) separately for Super High Tenacity (SHT) and Semi-dull on the basis of their tenacity/structure. This was done due to the fact that the price variation of the non-speciality types is essentially on account of tenacity. However, there is insignificant variation in the cost and price structure on account of deniers, length, luster or cross-section as far as the PUC is concerned. Petitioner companies are agreeable to comparisons on the basis of above mentioned product types or aggregate analysis as considered fit by the Authority.

### **Views of the Opposing Interested Parties**

- 5. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to Product Under Consideration:
  - i. The product under consideration is very broad and inaccurately defined considering the fact that the scope of the product under consideration covers multiple applications meant for various sectors.

- ii. The PUC has been incorrectly classified into Semi-dull and High Tenacity deliberately by the domestic industry for Price Effect and Dumping Analysis.
- iii. The “recycled PSF, non-dyed or dyed/coloured” should be clearly excluded from the scope of the product under consideration involved in the present investigation. The imports namely “100% Recycled Polyester Staple Fiber made from waste pet bottle flakes (Plastic Waste)” should be mentioned in the exclusion category.

#### **Examination by the Authority**

6. The Product under Consideration is “Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers, excluding recycled PSF and specialty fibres namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres”. It is clear that 100% Recycled Polyester Staple Fiber Made from Waste Pet Bottle Flakes (Plastic Waste)” is not covered in the scope of the PUC under the present investigation.
7. The above products are manufactured in various specifications defined in terms of their deniers, strength, lustres (like semi dull, bright, semi bright, full dull etc.), colour, cross section and cut length or staple length. The subject goods are predominantly used to spin yarn of 100% PSF or in blends with natural, artificial and/or synthetic staple fibres for manufacture of textiles, sewing thread, other industrial textiles, non-woven applications, etc.
8. The Authority had not notified any PCN or product types, nor did any interested party suggest the same. However, during the course of investigation, the examination of import data (from DGCI&S) and verification of domestic industry/exporters, it was noted that the subject goods could be broadly categorized as Semi-Dull polyester staple fiber and Super High-Tenacity polyester staple fiber. Further, in-depth examination of costing indicated that the difference in the cost of two categories of the products is less than 5% and hence the Authority decided that there is no need to undertake separate dumping and injury analysis.
9. Product under consideration is classified under HS Code 5503 20 00. However, the customs classification is indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.
10. The Authority notes from the information available on record that the Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that goods produced by the applicant domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries in accordance with the AD Rules.

#### **C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **Views of the Domestic industry**

11. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:
  - i. There are total four producers in India who are producing the subject goods namely M/s. Alok Industries Ltd., M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd., M/s. The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd. (Petitioners herein) and M/s. Reliance Industries Limited.
  - ii. That the only other producer of the subject goods apart from the petitioners herein, i.e. M/s. Reliance Industries Limited, has a related producer/exporter in Malaysia namely M/s. Recron (Malaysia) Sdn Bhd, who has exported the subject goods to India during the period of investigation. Therefore, Reliance Industries Ltd. should not be considered as a part of the Domestic Industry in terms of the Rule 2(b).
  - iii. In view of the fact that M/s Reliance Industries Ltd. is an ineligible producer, the applicants constitutes 100% of the total production of the eligible domestic producers in the country.

- iv. The applicants have not imported the product under consideration. The applicants are not related to any importer or exporter of the product under consideration from the subject countries. In any case, there is no such relationship that would attract possibilities of exclusion under Rule 2(b).
- v. Apart from the producers mentioned above, there is no other known producer of product under consideration in India. The petition satisfies the requirement of standing under the Rules. Further, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Anti-Dumping Rules.
- vi. The claims of the interested parties that Reliance Industries Ltd. should not be excluded from the scope of domestic industry because its related party 'Recron' has exported insignificant quantities of product under consideration during the period of investigation is misplaced. There are two conditions for eligibility of a domestic producer in terms of Rule 2(b) i.e., relationship of the producer with exporter/importer of subject goods and imports by the domestic producer. As a matter of fact the criteria regarding quantity has been applied by Authority invariably in the context of the second part i.e., the imports by the domestic producer. However, it is submitted that quantity is not a relevant criteria with respect to relationship of the domestic producer with exporter/importer of subject goods in terms of Explanation i(a) of Rule 2(b). Since Recron is a 100% subsidiary of Reliance, inclusion of Reliance in the scope of domestic industry is not permissible in terms of Rule 2(b).
- vii. The opposing parties have completely misinterpreted the Explanation to Rule 5(3) of the Rules. Under the provisions of Rule 5(3) there is no requirement which necessarily makes 50%+ support to the petition mandatory, especially when there is no opposition to the petition. As per the provision of Rule 5(3) the petitioner/s is/are required to have minimum of 25% of the share in the total production of the subject goods or the like articles in the country. However, it is for the purpose of deciding the support or opposition to the petition that the Rule further requires support by 50%+ portion of the domestic industry "either supporting or opposing the petition". In view of the fact that in the present case there has been no support/opposition to the petition, the requirement of 50% test becomes non-applicable.
- viii. Further, it has been supported by findings of the WTO panel that the arguments of the interested parties that the domestic industry necessarily need to have more than 50% of share in total domestic production is legally flawed and misplaced. In the context of the Anti-Dumping Agreement, the panel in Argentina - Poultry case had an occasion to consider whether or not the phrase "a major proportion" implies that the "domestic industry" refers to domestic producers whose collective output constitutes the majority, that is, more than 50 percent, of domestic total production. The panel considered different dictionary definitions and noted that the word "major" is also defined as "important, serious, or significant". The Panel therefore found that "an interpretation that defines the domestic industry in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production is permissible. The observations made thereunder by Panel in Argentina -Poultry are as under:

*7.341 In considering these different dictionary definitions, we note that the word "major" is also defined as "important, serious, or significant". Accordingly, an interpretation that defines the domestic industry in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production is permissible. Indeed, this approach is entirely consistent with the Spanish version of Article 4.1, which refers to producers representing "una proporción importante" of domestic production. Furthermore, Article 4.1 does not define the "domestic industry" in terms of producers of the major proportion of total domestic production. Instead, Article 4.1 refers to producers of a major proportion of total domestic production. If Article 4.1 had referred to the major proportion, the requirement would clearly have been to define the "domestic industry" as producers constituting 50+ per cent of total domestic production. However, the reference to a major proportion suggests that there may be more than one "major proportion" for the purpose of defining "domestic industry". In the event of multiple "major proportions", it is inconceivable that each individual "major proportion" could – or must – exceed 50 per cent. This therefore supports our finding that it is permissible to define the "domestic industry" in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion*

*of total domestic production. For these reasons, we find that Article 4.1 of the AD Agreement does not require Members to define the “domestic industry” in terms of domestic producers representing the majority, or 50+ per cent, of total domestic production.*

*7.342 There is nothing on the record to suggest that, in the circumstances of this case, 46 per cent of total domestic production is not an important, serious or significant proportion of total domestic production. Accordingly, we reject Brazil's claim that Argentina violated Article 4.1 of the AD Agreement by defining “domestic industry” in terms of domestic producers representing 46 per cent of total domestic production. (emphasis added)*

- ix. Further, the panel in the safeguard case of *US — Wheat Gluten* had the occasion to examine the link between the phrase “a major proportion” and the question of data coverage:

*“[T]he Agreement expressly envisages that, in certain circumstances, the ‘domestic industry’ may consist of those domestic producers ‘whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products’. This implies that complete data coverage may not always be possible and is not required. While the fullest possible data coverage is required in order to maximize the accuracy of the investigation, there may be circumstances in a particular case which do not allow an investigating Authority to obtain such coverage.”*

- x. The interested parties had also filed a Writ petition in Hon’ble Madras High Court seeking quashing of the initiation on the grounds of inadequate standing of the domestic industry in terms of the Rules. The Hon’ble Court decided not to interfere with the proceedings of the present case and only directed the Authority to hold a hearing of the interested parties and proceed with the case as per the provisions of law. The interested parties are attempting to misguide the Authority by presenting the outcome of the case in a distorted manner with a motive to change the course of investigation.

### **Views of the opposing interested parties**

12. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to standing and scope of domestic industry:

- i. The petition is not maintainable and the present investigation ought to be terminated as the threshold requirement of Domestic industry standing of the petitioner has not been met with.
- ii. For the purpose of initiating the investigation, one of the major producers, M/s Reliance industries limited has not been included.
- iii. M/s Reliance industries limited has been intentionally excluded from the scope of domestic industry in view of the fact that they have reported substantial profits from the sales of product under consideration in the domestic market during the period of investigation.
- iv. Reliance cannot be excluded merely on the ground that they have a related exporter/importer in the subject country, such a view is against the view taken by the Authority in the recent case of soda ash.
- v. The Applicants lack the requisite domestic industry standing for maintaining the present Application since Reliance Industries Ltd. ("RIL"), which is a major producer of PUC in India, has neither filed nor supported the present Application.
- vi. The total exports of Product under consideration from Recron, the related producer of RIL in Malaysia have been minimal. Therefore, the exclusion of Reliance is impermissible under law.
- vii. It is submitted that while the Applicants have stated in their Application that RIL cannot be considered a part of the domestic industry on account of its relatedness with Recron, a related exporter, on the contrary, one of the Applicants, i.e., M/s. Indo Rama Synthetic (India) Ltd., has filed the present Application in the capacity of representing the domestic industry despite it being related to an exporter, namely, M/s. P.T. Indorama Synthetics Tbk. Indonesia.
- viii. It is submitted that in the past, this Authority has itself considered the volume of total imports from a related exporter in relation to the total imports of PUC, total domestic production of PUC

and the total demand of PUC, when determining whether or not the imports from the related exporter is significant so as to warrant exclusion of a domestic producer with a related exporter from the ambit of domestic industry.

- ix. The exclusion of RIL, which holds the *major proportion* of total domestic production of PUC in India, without testing such exclusion against the tests provided Rule 2(b)(1)(c), is a patent error in law and jurisdiction.
- x. With regard to the interpretation of the phrase *major proportion* in the definition of *domestic industry*, it may be noted that the WTO Appellate Body in its finding dated 18 January 2016 in *Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron & Steel Fasteners from China*, has observed that while establishing whether applicants hold a *major proportion* of the domestic production of PUC so as to constitute domestic industry, Authority has to be careful that this does not introduce a material risk of distortion of injury. It was further observed that the lower the proportion of domestic production, the more sensitive an investigating Authority will have to be to ensure that the proportion used substantially reflects the total production of the producers as a whole.
- xi. In the WTO Panel Finding in *China - Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from The United States*, the Panel noted that an investigating Authority is not allowed to ignore the situation of other domestic producers in its injury determination. An investigating Authority will make its analysis under Articles 3.2 and 3.4 with reference to the defined domestic industry, but will still need to assess the situation of other domestic producers in its evaluation of whether it is the impact of the subject imports that have explanatory force for the changes in the various economic factors and whether the strength of other domestic producers could be a possible separate cause of injury to the defined domestic industry.
- xii. According to Article 5.4 of the ADA and the Explanation to Rule 5(3) of the Rules, an application must be supported by domestic producers whose collective output constitutes *more than 50% of the total production* of the 'like product' expressing either support for or opposition to the application.
- xiii. It is submitted that in the Explanation under Rule 5(3)(b) it is categorically stated that the Applicants shall only be considered as Domestic Industry if the collective output of the Applicants is more than 50% of the total Domestic Producers. Hence, in the case at hand the Applicants themselves admit that their share in the domestic production is only 43% which is much less than the limit prescribed under law.
- xiv. The judgement of Madras HC in *Nirma Ltd. V. Saint Gobain Glass India Ltd.* held that the amendment in Sec 2(b) has not taken away discretionary power from DA. However, it is again reiterated that the learned DA is required to carry out an analysis accurately and adequately of the data while using its discretionary power and pass a speaking order while conducting the prima facie determination and failure to do the same amounts to the initiation notification being bad in law.
- xv. The DA has full discretion to adjudge the “Domestic Industry” and in a case such as the present one where the majority share i.e. more than 50% belongs to a party who might be related to an importer should be included in the purview of “Domestic Industry”. It will not be out of context here to mention that as per the Applicants they enjoy only 43% of the total domestic production of the PUC. Hence it is already admitted by the Applicants that they do not have the requisite 50%.
- xvi. The following three conditions have to be clearly rebutted by the complainants to prove themselves as DI :
  - a) Not an importer itself – Reliance is not an importer
  - b) Not related to importers – Reliance is not related to importers
- xvii. Recron has insignificant export of PUC to India– Perusal of exporter questionnaire of M/S Recron indicates that it has insignificant exports in India to independent customers when compared to the

domestic production of its related company Reliance Industries Limited which establishes Reliance as genuine producer in India.

- xviii. The importers had challenged the initiation notification dated 02.02.2017 before the Hon'ble Madras High Court by way of Writ Petition no. 17926/2017, 17927/2017 and 17937/2017. The Hon'ble court has decided the matter and the relevant part of the order is reproduced herein below for ready reference:

*“24. It is interesting to take note the decision in the case of Arun Kumar and others vs. Union of India and others reported in (2007) 1 SCC 732, wherein the Honble Supreme Court explained the term jurisdictional fact. Jurisdictional fact is a fact which must exist before a court, tribunal or an Authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an Authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, Authority or officer cannot act. If a court or Authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by a writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no Authority can confer upon itself jurisdiction which it otherwise does not possess.*

*25. Thus, in the light of the above decision, if at the inception of an enquiry by a Tribunal or an Authority, a challenge has been made to the jurisdiction, the Tribunal/Authority has to take a decision as to whether or not to act and give a ruling on the preliminary or collateral issue, but such ruling is not a conclusion. Above all, the rules are clear, especially Rule 12 of the Customs Tariff Rules and there is no necessity for this Court to issue any direction to the first respondent to decide the matter in a particular manner nor it would be right in doing so, as he is cast with a statutory duty to determine the injury based on relevant consideration, which undoubtedly would mean as to whether the fifth respondent has to be excluded from the proceedings or not. It would be sufficient to direct the first respondent to hear all the interested parties including the petitioners/association and the individual writ petitioner as well as other petitioner and proceed in accordance with law.”*

- xix. From the bare perusal of the aforesaid order it is evident that the Hon'ble High Court has held that the Learned DA has to first satisfy itself with the issue of jurisdiction, which can be done by making the said point as a preliminary issue.

### **Examination of the Authority**

13. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

14. The application has been filed by M/s Alok Industries Ltd., M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd. and M/s. The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd. as domestic producers of the product under consideration. The Authority had noted the fact stated in the petition that the fourth producer M/s. Reliance industry Ltd. is having a related party in one of the subject countries and hence is not eligible to be a domestic industry in terms of Rule 2(b). The three petitioner companies have neither imported the subject goods nor are related to any of the exporters or importers of the subject goods from subject countries. The fact of their relationship with other Indorama companies in Indonesia and Thailand has been verified from the documents submitted by the petitioner company and also the exporters there who have fully co-operated in the investigation. M/s. P.T. Indorama Synthetics Tbk, Indonesia and M/s. Indorama Polyester Industries PCL, Thailand are related to each other but are not related to the Indian petitioner company M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd.
15. It was observed by the Authority that M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd, Malaysia is a 100% subsidiary of Reliance Industries Ltd, India. This fact was verified from the documents submitted by the exporter,

hence the fact of relationship is fully established. Further, the details of exports made by M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd were verified from DGCI&S data. The details of exports by M/s. Recron Malaysia to India and import by Reliance Industries are as below.

S.N.	Particulars	Quantity (in MT)	Imports by Reliance Quantity (in Kgs)
1	China	52,261	743
2	Indonesia	10,900	-
3	Malaysia	5,251	-
3a	Exports by M/s Recron Sdn Bhd	274	-
4	Thailand	6,867	-
5	Total Subject Countries	75,279	743
6	Other Countries	8,901	7,600
7	Total Imports	84,181	8,343

16. The data clearly indicates that M/s Recron, Malaysia has exported to India to the end-users of the subject goods as well as M/s. Reliance Industries Ltd., India has made imports from China. Therefore, the Authority was within their right in terms of Rule 2(b) to exclude M/s. Reliance from the scope of domestic industry at the time of initiation.
17. The petitioners had clear standing to file the present petition when examined in terms of Rule 5(3) of the Rules. The share of three producers forming the domestic industry constitute 49% of the Indian production during the POI and M/s. Reliance Industries Ltd. constitute 51% of the Indian production, who had neither submitted data nor opposed the petition. Since there was no opposition to the petition, the three producers namely, M/s. Alok Industries Ltd., M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd. and M/s. The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd have clear standing which was above the eligible limit of 25% as required under Rule 5(3).
18. Subsequent to the initiation, the Authority received several representations from the importers/users stating that data pertaining to costing and finance should be called for analysis from M/s. Reliance Industries Ltd. and they should be treated as the domestic industry for the purpose of present investigation as it will have great implication on overall cost/financial data leading to injury analysis.
19. Keeping in view the specific request of the importers/users to consider the costing and financial data of M/s. Reliance Industries while calculating domestic industry pricing; the Authority wrote a letter to M/s. Reliance Industries, seeking information regarding their production, exports, imports, costing and financial data. In response to the letter, M/s. Reliance Industries Ltd. stated that :
 

*“since the sole exporter of Malaysia M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd is a related company being our wholly owned subsidiary. Therefore, we are not part of the domestic industry.*

*However, we have no objection to domestic industry pursuing the case and your proceeding with the matter.”*
20. Further, the examination of import data had revealed that M/s. Reliance Industries Ltd. has imported the subject goods from China during the POI (detailed in above para), which is also one of the subject countries in the present investigation, rendering them ineligible as domestic industry under Rule 2(b).
21. In view of the admitted fact that Reliance Industries Ltd. has a related exporter (100% Subsidiary) in one of the subject countries combined with the fact that Reliance Industries Ltd. has also imported the subject goods from China during the POI, the Authority considers it appropriate to not treat M/s. Reliance Industries Ltd as eligible Domestic Industry and consider the rest of the domestic producers as ‘Domestic Industry’ in terms of the proviso to Rule 2(b). Further, it is noted that the applicants also have clear standing in terms of Rule 5(3).



22. The submission of the interested parties regarding the requirement of more than 50% support to the petition, is not relevant in the present case where there is no opposition to the petition and the petitioner companies are holding around 49% portion of domestic industry.
23. The case on WTO jurisprudence in the subject-matter as quoted by opposing interested parties was noted and it is observed that the standing in the present case is lawful and has been arrived at with due caution. The Appellate Body Report in *EC – Fasteners* relied upon by interested parties merely states that "a major proportion" should serve as a "substantial reflection of the total domestic production". This does not imply that the "major proportion" ought to be the total production by itself or even closer to the total production. Interestingly, the Appellate Body in the same case has also cautioned that "the lower the proportion, the more sensitive an Investigating Authority will have to be to ensure that the proportion used substantially reflects the total production of the producers as a whole", thereby implying that a lower proportion can also be sufficient to fulfill the requirement of Article 4.1(c) so long as it ensures that it should substantially reflect the total domestic production.
24. The decision of the Hon'ble Madras High Court has been thoroughly understood and it is clear that the Hon'ble Court decided to not issue any specific directions to the Authority and has left it to the Authority to determine the injury based on relevant consideration in terms of relevant Rules. The Hon'ble Court has only considered it sufficient to direct the Authority to hear all the interested parties, which has been duly complied with by the Authority by holding an oral hearing on 23.11.2017 inviting all the interested parties to attend the hearing and present their case orally followed by written submissions. The said opportunity of hearing has been availed by all the concerned interested parties, personally and/or through their legal representatives/associations.
25. In view of the above, after detailed examination the Authority has decided that the petitioner companies constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2(b). Further, the petitioner companies also have the standing in terms of Rule 5(3) to file the present petition.

#### **D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

##### **Views of the Domestic industry**

26. The submissions made by domestic industry are as follows:
  - i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
  - ii. The petitioner has provided proper non-confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information where confidentiality has been claimed which is not justified under the Rules.
  - iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in an indexed form as the information is business proprietary information and hence confidential in nature.
  - iv. None of the exporters has provided the non-confidential version of their responses which is an exact replica of their confidential version. They have kept all the volume related information confidential. They have also not provided any statement of claim of confidentiality. Further, the responses are in stark violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of the exporter's questionnaire responses. The Domestic Industry, therefore, request the Authority to disregard the submissions of the interested parties and also to reject the responses of exporters and deny them the individual treatment.

##### **Views of the opposing interested parties**

27. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
  - i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to volume related information also.

- ii. The domestic industry has claimed and has been allowed excessive confidentiality in the sense that they have not made available their annual report in the public file.
- iii. Domestic Industry has also not provided sufficient details of their costing.

#### **Examination by the Authority**

28. The Authority made available non confidential version of the information provided by various parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
29. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the justification of their claims and the specific provisions of law as interpreted by the Hon'ble Supreme Court. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

### **E. MISCELLANEOUS ISSUES**

#### **Views of the Domestic Industry**

30. The submissions of domestic industry parties are summarized as follows:
  - i. The responding producers have withheld vital information regarding their related parties involved in the production, sales and procurement of inputs therefore their response should be rejected and they should not be granted individual dumping margin.
  - ii. The subject goods constitute around 45-50% of the total cost of the yarn which is then consumed in shirting, suiting and other garments. The impact of imposition of anti-dumping duty is insignificant compared to the cost of the finished goods, e.g., a duty of 10% on the subject goods will entail increase in fabric cost in the range of 0.57- 1.3 % in case of shirting and 1.2 -2.3 % in case of suiting.

#### **Views of the opposing interested parties**

31. The submissions of various interested parties are summarized as follows:
  - i. The petition filed by the petitioners is based on unreliable and inaccurate data.
  - ii. Reason for increase in imports of product under consideration during the period of investigation is quality issues in the product supplied by the petitioners.
  - iii. Application filed by the domestic industry is deficient as it lacks the evidence and the information as required under the law and therefore, the same cannot be considered as a valid and fully documented application. In terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules, the Hon'ble Designated Authority is obligated not to initiate an anti-dumping investigation unless (a) it determines that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and (b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link to justify initiation. The determinations that the application has been made by or on behalf of the domestic industry producing the like product and there is dumping, injury and causal link are the conditions precedent which ought to be fulfilled prior to the initiation of the investigation.
  - iv. The domestic industry has used unrealistic and unreliable import figures in the application filed by them.
  - v. The Soft Copy of Import data in excel file has not been provided. Also, domestic industry has not provided the copy of Original/Raw transaction-wise import data obtained from IBIS.
  - vi. If anti-dumping duty is levied on PSF, then 5% duty on the PSF will raise the price to the tune of around Rs.5 and 10% duty will raise the price to the tune of around Rs. 10.5 affecting the yarn industry. As the cost of yarn in international market will remain unaffected, it is only the Indian market that will suffer by the levy of duty and the yarn

industry will have to bear the brunt of this imposition of duty. This in turn will create extra cost and burden for the Indian industry as a whole and not just limited to PSF or PUC which will have a cascading impact on the industry.

- vii. The total demand of the subject goods are more than the production of the Domestic Industry, thus imports are inevitable.

#### **Examination by the Authority**

32. The miscellaneous submissions have been examined as under:

- i. The contention that the petition filed by the domestic industry is based on incorrect data, is baseless and unsubstantiated. In any case, it may be mentioned that the Authority had initiated the investigations after being fully satisfied about the evidence presented by the Domestic Industry and when Authority had arrived at prima facie conclusion that there is sufficient evidence to justify the initiation of the investigation. The Authority also satisfied itself about the accuracy and the adequacy of the data/information which was necessary to initiate investigations in terms of Rule 5. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission made by the interested parties.
- ii. The contention that the increase in imports during the period of investigation was on account of quality issues in respect of the products sold by the domestic industry is unsubstantiated. In any case, the Authority has already considered that the goods offered by the domestic industry and the imported goods are 'like articles' and they compete in the same market. Further, the Authority has consistently held that quality *per se* is not a determinative factor for the purpose of anti-dumping investigations.
- iii. As regards the submission of the interested parties regarding imports data (DGCI&S), the Authority notes that a printed copy of the imports data was kept in the public file, available for inspection by the interested parties, and the records show that most of the interested parties have taken the copy of data for their records. Also, it is a practice of the Authority to authorise the parties to collect DGCI&S import data (in soft copy) on receipt of a request by interested parties, however, none of the interested parties have submitted any request to the Authority asking for imports data in the present investigation at any time.
- iv. As regards the soft copy of the IBIS data, the Authority notes that IBIS data was a part of the petition filed by the domestic industry. A soft copy of the petition was provided to all the listed interested parties and to other interested parties upon request. A copy of the petition was also kept in the public file which was open for inspection by the interested parties. Therefore, the contentions of the interested parties regarding present issue are baseless.
- v. The domestic industry has given detailed calculations for the impact of Anti Dumping Duty on the downstream industry and it is noted that the impact is not significant. Further it is noted that anti-dumping duty is to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry.
- vi. The total demand in POI (18 months) is 1,209,242 MT which is a sum of total domestic sales (applicants and others) and total imports (subject countries and others). The total installed capacity in India is sufficient to cater the present demand, moreover, the idea of Anti-dumping duties is not to block imports but rather create a fair and level playing field for exporters and Domestic Industry.

#### **F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

##### **Normal Value**

##### **Views of the Domestic industry**

33. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. In terms of Para 8 of Annexure I of the anti-dumping rules, China has to be presumed to be a Non-market Economy Country unless the concerned firms/producers/exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria spelt out in Para 8(3). This is also in line with the position taken

by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value. The domestic industry respectfully submit that

ii. China PR should be treated as nonmarket economy country for the following reasons:

- a) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
- b) Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
- c) Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. Contrarily, while examining material injury existence of a single parameter is considered sufficient to establish such injury. In other words, where one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
- d) It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- e) Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- f) It has been submitted that the normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules without invoking proviso to 8(2) in view of the aforementioned facts and circumstances.
- g) The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. It is also submitted that since these options for determination of normal value are available, the Designated Authority may not kindly consider "any other basis" because this is required to be applied only when other basis listed under the law cannot be applied.
- h) Exporters namely Fujian Jingwei, Jiangyin Huahong and Jiangyin Hailun, have only claimed the MET status which too is not complete and hence liable to be rejected. China is a non-market economy country. None of the exporters satisfy each and every condition to qualify for grant of market economy status.
- i) The Chinese exporters have also withheld information regarding related parties and the company shares and which can influence the decisions of the company through its board of directors. In view thereof, the Domestic Industry requested the Authority to reject the MET claim of the company.
- j) The responding producers from China have not provided their complete value chain as their related entities in China have not participated in the investigation.
- k) The responding producers/exporters from China have conveniently omitted to provide any information as to the subsidies received by them by the Government of China. The balance sheet of the Chinese producers and the investigations carried out by United States in the case of Fine denier PSF clearly show that the Chinese producers have taken benefit from the subsidies provided by the Chinese Government. The omission of such critical piece of information by the Chinese producers amounts to misleading the Authority and renders all the information filed by them dubious. Therefore, the same must be rejected for the want of complete and correct information.

- l) Para 8(2) of Annexure-I leaves no choice for the Designated Authority but to presume China to be a Non-Market Economy country. However, the same is open to rebuttal by the Chinese firms under the provision of Para 8(3).
- m) The Designated Authority is a creation of the statute and has to perform its obligations and exercise the powers as specifically assigned to it under the specific provisions of the statute. Therefore, unless the provisions of Para 8 are amended, it is imperative for the Designated Authority to operate as per the procedure mentioned in Para 8 and presume China as a Non-Market Economy country.
- n) The significant extent of continued government intervention in certain important sectors of the Chinese economy warrants maintaining China's designation as a Non-Market Economy country. It is a known fact that China's economy is controlled by the state forces and there is a significant interference and control of the state machinery in the country's economy. The grant of Market Economy status under China's accession to the WTO is not automated but contingent upon China's compliance with the preconditions mentioned in the Accession Protocol.
- o) As for Indonesia, the responding producer/exporter, M/s. PT. Indo-rana synthetics TBK, Indonesia has furnished incomplete information regarding related parties, shareholdings, and raw material supply. They have not provided information about its related companies supplying major raw materials used to produce the subject goods. Their website clearly shows that the company has a related party, PT. Indorama Petrochemicals which is a manufacturer of Purified Terephthalic Acid, the major raw material for the production of subject goods. PT. Indo-Rama Synthetics TBK has not provided their complete value chain as their related entities have not participated in the investigation. Therefore the Authority is requested to reject their response and not consider them for individual dumping/injury margin.
- p) As for Thailand, the responding producer/exporter M/S Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd. has not provided their complete value chain as their related entities have not participated in the investigation. The response filed by responding producer/exporter, M/S Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd. clearly reveals that they have bought raw materials from their related parties. They have not provided information about its related companies supplying the main raw materials used to produce the subject goods. Therefore, the information submitted by them as to costs etc. cannot be trusted. Therefore the Authority is requested to reject their response and not consider them for individual dumping/injury margin.

#### **Views of the Opposing Interested Parties**

34. The following interested parties from China, Indonesia, Thailand, and Malaysia have filed detailed responses and submissions with regard to Normal Value and export price.

1. M/s Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd, China
2. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China
3. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd., China
4. M/s Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co. Ltd., China
5. M/s Xiamen MC Group (HK) Corp. Ltd., China
6. M/s Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd., China
7. M/s Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd., China
8. M/s United Raw Material PTE Ltd., China
9. M/s PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia
10. M/s Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand
11. M/s Recron (Malaysia) Sdn Bhd., Malaysia

35. Following parties from China PR have claimed Marker Economy Treatment:

1. M/s Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd.
2. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd.
3. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd

36. In addition to their claim of market economy treatment, the parties have stated that as per Section 15(a) (ii) of protocol on the Accession of the China PR to the WTO expired on December, 2016 and after that date, India no longer has legal basis under the agreements of the WTO to calculate normal value in anti-dumping investigation of Chinese products using the non-requirements of agreement on implementation of article VI of the general agreement on tariff and trade, 1994 and other covered agreements.

**Examination by the Authority**

37. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Several producers and exporters from the subject countries have filed the prescribed questionnaire responses.
38. It was alleged by the domestic industry in their application that Chinese companies continue to operate on non-market economic conditions. Based on the claims of the domestic industry, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status to demonstrate that they are operating under market economy conditions. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters from China for providing sufficient information. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide all the relevant information.
39. The following producers from China, along with some of their exporters/traders, have filed the prescribed questionnaire responses.
1. M/s Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd.
  2. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd. along with its trader M/s United Raw Material PTE Ltd.
  3. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.
  4. M/s Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co. Ltd.
  5. M/s Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. along with its traders M/s United Raw Material PTE Ltd. and M/s Xiamen MC Group (HK) Corp. Ltd.
  6. M/s Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd.
40. The Supplementary questionnaire response was filed by the following producers/ exporters from China.
1. M/s Fujian Jingwei New Fiber Science And Technology Co. Ltd.(Jingwei)
  2. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd.
  3. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.
41. The domestic industry made another representation post initiation, stating that the Chinese companies are not operating under the market economy conditions and there is significant government control in Chinese market. Therefore, their cost cannot be trusted for the computation of normal value.
42. The Authority has taken cognizance of the information provided by the respondent Chinese companies who have filed MET supplementary questionnaire response wherein they have sought to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure 1 of the Anti-dumping Rules. The Authority notes that the responding companies have failed to provide sufficient evidence to establish that they are operating under market economy conditions.
43. The Authority further notes that the responding companies have not provided sufficient details in their response in respect of their Holding/group companies, the source of raw materials, reliability of exchange rates and other relevant information to establish that they are operating under market conditions. In view of the above, the Authority cannot grant market economy treatment to the above stated respondent Chinese companies.
44. The Authority therefore, holds that none of the producers/exporters from China PR has been found to be operating under market economy conditions for determination of normal value in China in terms of Para-6 of Annexure-1 to the Rules. Under the circumstances, the Authority is not in a position to apply Para 8

of Annexure 1 of the Rules to the above named Chinese companies and the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules.

45. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No such information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country at this stage. Therefore, for the purpose of determination of Normal Value, the Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis.
46. The Authority constructed the Normal Value for China PR on available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration is determined based on constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The constructed normal value determined is as mentioned in the dumping margin table below.

#### **I. EXPORT PRICE IN CASE OF CHINA PR**

##### **M/s. Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd.,**

47. M/s. Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd has filed Exporters Questionnaire Response claiming themselves a producer and exporter of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed by M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd., it is noted that they have exported \*\*\* MT of the subject goods to India during the POI, out of this \*\*\* MT has been exported directly and \*\*\* MT has been exported through unrelated exporters/traders, namely, M/s. United Raw Material, Singapore (\*\*\* MT) and M/s Triveni Spinning Mil, Nepal (\*\*\* MT). M/s United Raw Material, Singapore, in turn has exported (\*\*\* MT) directly to India and rest (\*\*\* MT) has been exported through another trader namely M/s. Astral Overseas Pte Ltd., Singapore, who have not filed Exporters Questionnaire responses with the Authority.
48. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for majority of the quantity exported to India directly or indirectly, and accepted the quantity for which Exporters Questionnaire responses have been filed. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, ocean freight, overseas freight, bank charges, credit and the same have been accepted after necessary verification. The net export price is determined as below.

Constructed Normal value USD/MT	Net Export Price USD/MT
***	***

##### **M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co., Ltd.,**

49. M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co., Ltd., China PR has filed Exporters Questionnaire Response claiming themselves a producer and exporter of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed, M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co., Ltd., China PR has exported \*\*\* MT of the subject goods to India during the POI, out of this \*\*\* MT has been exported directly and \*\*\* MT has been exported through unrelated exporters/traders namely M/s. United Raw Material, Singapore (\*\*\* MT), M/s. Triveni Spinning Mil, Nepal (\*\*\* MT), M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Nepal (\*\*\* MT) and M/s. Xiamen MC Group (HK) Corp. Ltd., Hong Kong (\*\*\* MT). Only M/s. Triveni Spinning Mil, Nepal (\*\*\* MT) and M/S Reliance Spinning Mills Ltd., Nepal (\*\*\* MT) have not filed their Exporters Questionnaire responses with the Authority.

50. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for majority of the quantity exported to India directly or indirectly, and accepted the quantity for which Exporters Questionnaire responses have been filed. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, ocean freight, overseas freight, bank charges, credit and the same have been accepted after necessary verification. The net export price is determined as below.

Constructed Normal value USD/MT	Net Export Price USD/MT
***	***

**M/s. Fujian Zhengqi High-tech Fiber Technology Co., Ltd.**

51. M/s. Fujian Zhengqi High-tech Fiber Technology Co. Ltd., China PR has filed Exporters Questionnaire Response claiming themselves a producer and exporter of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed by M/s. Fujian Zhengqi High-tech Fiber Technology Co. Ltd., it is noted that they have exported \*\*\* MT of the subject goods to India during the POI, out of this \*\*\* MT has been exported directly and \*\*\* MT has been exported through exporter/trader namely M/s. Tionale Pte., Ltd., Singapore who has not filed Exporters Questionnaire responses with the Authority.
52. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for majority of the quantity exported to India directly or indirectly, and accepted the quantity for which Exporters Questionnaire responses have been filed. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, ocean freight, overseas freight, bank charges, credit and the same have been accepted after necessary verification. The net export price is determined as below.

Constructed Normal value USD/MT	Net Export Price USD/MT
***	***

**M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fibre Co. Ltd. China PR**

53. M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co., Ltd. has filed EQ Response claiming themselves a producer and exporter of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed by M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co., Ltd., it is noted that they have exported a total of \*\*\* MT of the subject goods during the POI. Out of which the direct exports by them in the POI were \*\*\* MT and remaining exports of \*\*\* MT were through unrelated traders, who has not filed the response.
54. The Authority examined the Exporters Questionnaire response and noted response has been filed for majority of the quantity exported to India directly or indirectly, and accepted the quantity for which Exporters Questionnaire responses have been filed. The exports details furnished by producer have been considered for determining ex-factory export price for grant of individual dumping and injury margin. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, ocean freight, overseas freight, bank charges, credit and the same have been accepted after necessary verification. The net export price is determined as below.

Constructed Normal value USD/MT	Net Export Price USD/MT
***	***



**M/s. Fujian Jingwei New Fiber Science & Technology Co. Ltd**

55. M/s. Fujian Jingwei New Fiber Science & Technology Co. Ltd has filed Exporters Questionnaire Response claiming themselves a producer of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed by M/s M/s. Fujian Jingwei New Fiber Science & Technology Co. Ltd., it is noted that they have exported entire quantity of the subject goods to India through an unrelated exporter M/s MGSGC & S LLC DBA Seven Hills Imports, USA, during the POI. Further, it is noted that the exporter/trader has not filed its Exporters Questionnaire responses with Authority. In absence of the complete response by the producer and the exporter, the Authority is unable to accept the response for grant of individual dumping and injury margin.

**M/s Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.**

56. Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. has filed Exporters Questionnaire Response claiming themselves a producer and exporter of subject goods from China PR. From the Appendix-2 filed it is noted that they have exported a total of 2424MT of the subject goods to India during the POI. Out of which the direct exports by them were 2% and remaining 98% exports were through unrelated traders, who have not filed its Exporters Questionnaire responses with Authority. In absence of the complete response by the producer and the exporter, the Authority is unable to accept the response for grant of individual dumping and injury margin.

**II. INDONESIA****Normal Value for M/s PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia**

57. The questionnaire response filed by the exporter has been examined. The same is complete and in order. The cost of production was determined on the basis of verified information of the producer and domestic sale transactions were examined and found that the domestic sales are in the ordinary course of trade. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on complete domestic sales data. Producer has claimed adjustment on account of transportation, credit cost, insurance and the same have been accepted after necessary verification. The normal value is to be determined as below.

**Export price in case of M/s PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia**

58. During the POI, M/s. PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia, has exported the subject goods to India directly. The exporter has claimed adjustment on account of commission, inland transportation, overseas transportation, bank charges, credit cost and the same have been accepted after necessary verification. The net export price is to be determined as below.

Normal value USD/MT	Net export Price USD/MT
***	***

**III. THAILAND****Normal value and Export Price for M/s Indorama Polyester Industries PCL,**

59. The questionnaire response filed by the exporter has been examined. The same is complete and in order. The cost of production was determined on the basis of verified information of the producer and domestic sale transactions were examined and found that the domestic sales are in the ordinary course of trade. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on complete domestic sales data. Producer has claimed adjustment on account of transportation, credit cost, insurance and the same have been accepted after necessary verification. The normal value is to be determined as below.

**Export price in case of M/s Indorama Polyester Industries PCL, Thailand**

60. During the POI, M/s Indorama Polyester Industries PCL, Thailand, has exported the subject goods to India during POI directly only. The exporter has claimed adjustment on account of commission, inland freight, ocean freight, oceans insurance, bank charges, credit cost, other expenses, export incentive and the same have been accepted after necessary verification. The normal value & net export price was calculated average basis and same is as below.

Normal value USD/MT	Net Export Price USD/MT
***	***

#### IV. MALAYSIA

##### Normal value and Export Price for M/s Recron Malaysia Sdn Bhd

61. M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd. has filed exporter questionnaire response. The same was examined and it is found that they have not sold the subject goods in Malaysia as is also clear from the Appendix 1 filed by them. Therefore, the normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the exporters after due verification.

##### Export price in case of M/s Recron Malaysia Sdn Bhd

62. During the POI, M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd, has shipped the subject goods directly to India. All the supporting export documents were made available for verification. The exporter has claimed adjustment on account of commission, inland freight, ocean freight, oceans insurance, bank charges, credit cost, other expenses, export incentive and the same have been accepted after necessary verification. The normal value & net export price was calculated average basis and same is as below.

Constructed Normal value USD/MT	Net export Price USD/MT
***	****

#### DUMPING MARGIN

63. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing normal value (constructed wherever the actual normal value is not available/acceptable) and net export price at ex-factory level for the subject goods.

S.N.	Producer	Exporter	NV/CNV	NEP	Dumping Margin		
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
CHINA							
1	M/s. Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China	1. M/s. Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China 2. M/s United Raw Material PTE Ltd.	***	***	***	***	15-25
2	M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.,	M/s. Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.,	***	***	***	***	15-25
3	M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd.	1. M/s. Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. 2. M/s. Xiamen MC Group (Hk) Corp. Ltd., 3. M/s. United Raw Material PTE Ltd.	***	***	***	***	20-30
4	M/s. Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd.	M/s. Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
INDONESIA							
5	Pt. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia	Pt. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia	***	***	***	***	15-25

S.N.	Producer	Exporter	NV/CNV	NEP	Dumping Margin		
THAILAND							
6	Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand	Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand	***	***	***	***	1-10
MALAYSIA							
7	M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd.	M/s. Recron Malaysia Sdn Bhd	***	***	***	***	15-25

64. It is seen that the dumping margin for the subject goods is above de-minimus from all the subject countries.

#### **G. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

##### **Views of the Domestic Industry**

65. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. Imports of the product under consideration have shown increase over the years with a significant increase in POI.
- ii. Market share of subject countries in demand is significant. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year. The same is due to significant imports from subject countries;
- iii. Domestic industry prices, reflect the effect of the prices that are being offered by the importers in the domestic market;
- iv. The price underselling, price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms. The main reason for this is high volume of imports from subject countries that too at dumped and injurious prices.
- v. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.
- vi. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from subject countries.
- vii. The decrease in selling price was more than the decrease in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- viii. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from subject countries. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue

##### **Views of the opposing interested parties**

66. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority :

- i. The Domestic Industry is not suffering any injury and has improved throughout the injury investigation period;
- ii. From the data furnished by the petitioners, they have failed to show any injury on account of allegedly dumped imports.
- iii. The petitioners have adopted the method of cumulative assessment of injury in the present case, which in present circumstances is inappropriate.

- iv. Requirement of positive evidence and objective examination by the investigating Authority in injury analysis under Article 3.1 of ADA, concerning three factors: firstly, volume of dumped imports; secondly, the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and; thirdly, the consequent impact of these imports on domestic producers of like products is obligatory on investigating Authority.
- v. The evidence submitted by applicants could not support a “significant” increase of imports either in absolute terms or in relative terms under Article 3.2.
- vi. Any injury allegedly suffered by the domestic industry has been caused by factors other than imports from the subject countries

### **Examination by the Authority**

67. The impact of the dumped imports on the domestic industry is to be examined in terms of Para (iii) and (iv) of Annexure-II of the AD Rules.
68. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigations and considered relevant by the Authority.
69. The Authority computed the non-injurious price in accordance with Annexure 3 to the Anti-dumping Rules and the established practices of the DGAD.
70. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II of the Rules supra.

### **I. Assessment of Demand**

71. For this purpose, demand or apparent consumption of the subject goods in India is taken as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all sources. Since the POI is for 18 months (April 2015 to September 2016), the data for POI has been annualized for effective comparison for earlier periods.

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	POI	POI-A
Imports from subject countries	MT	8,411	24,876	44,409	75,279	50,186
Imports from other countries	MT	2,584	3,780	4,224	8,901	5,934
Total Imports	MT	10,995	28,656	48,633	84,181	56,120
Domestic Sales-Applicants	MT	228,540	248,652	270,509	440,012	293,341
Domestic Sales-Others	MT	486,050	462,500	447,400	685,050	456,700
Total Domestic Sales	MT	714,590	711,152	717,909	1,125,062	750,041
Total Demand (MT)	MT	725,585	739,808	766,542	1,209,242	806,161
Trend	Indexed	100	102	106	167	111

72. The Authority notes that the total demand in India has increased in POI and over the entire injury period.

### **II. Volume Effect of Dumped Imports**

#### **Import Volume and Market Share in Imports**

73. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. Since the POI is for 18 months (April, 2015 to September, 2016), the data for POI then been annualised for effective comparison with earlier periods. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analysed as under:

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	POI (April 2015-Sept 2016)	POI- A
Imports from China	MT	6,261	20,632	33,956	52,261	34,841
Imports from Indonesia	MT	0	135	4,344	10,900	7,267
Imports from Malaysia	MT	2,046	1,999	2,204	5,251	3,501
Imports from Thailand	MT	104	2,111	3,904	6,867	4,578
Imports from subject countries	MT	8,411	24,876	44,409	75,279	50,186
Trend	Indexed	100	296	528	895	597
Imports from other countries	MT	2,584	3,780	4,224	8,901	5,934
Trend	Indexed	100	146	163	344	230
Total Imports	MT	10,995	28,656	48,633	84,181	56,120
Trend	Indexed	100	261	442	766	510
<b>Share in Total Imports</b>						
Of Subject Countries	%	76	87	91	89	76
Of Other Countries	%	24	13	9	11	24

74. The share of imports from subject countries in total imports is around 89%. The balance 11% of the imports are from South Korea and Taiwan besides others are having insignificant share. The imports from South Korea and Taiwan are at higher prices not causing injury to the domestic industry. It is noted from the above table that imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms during the injury period and the POI, however, the share of imports from subject countries in total imports has not shown any significant changes during POI (annualized) as compared to the previous years.

### **III. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**

75. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

#### **a. Price Undercutting**

76. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the landed price of imports (as per DGCI&S data) has been compared with net sales realization of the domestic industry.

Particulars	Unit	Total
Landed Price of Imports from Subject Countries	Rs/MT	71,856
Net Selling Price	Rs/MT	***
Price Undercutting	Rs/MT	(***)
Price Undercutting	%	(***)
Price Undercutting	Range	(5)-5

77. The analysis indicates that the landed value of imports from all the subject countries (cumulatively) is higher than the net selling price of DI in India and hence price undercutting is negative.

**b. Price Underselling**

78. Price underselling suffered by the domestic industry has been examined by comparison of landed price of imports with NIP.

Particulars	Unit	Total
Landed Value of imports from Subject Countries	Rs/MT	71856
NIP	Rs/MT	***
Price Underselling	Rs/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	1-10

79. It is noted that the imports from subject countries are landing at price lower than the NIP and hence there is a positive underselling.

**c. Price Suppression and Depression**

80. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the petitioner has given data of cost of sales and selling prices and considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
Landed Value of Imports of Subject countries	Rs./MT	93,138	98,959	88,634	71,856
Index	Indexed	100	106	95	77
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	92	78
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	94	79

81. It is seen that the cost of sales of Domestic Industry for subject goods is decreasing during the entire injury period and POI except a hike in year 2013-14. The selling price of the Domestic Industry is also decreasing. Further, it is noted that the selling price is below the cost of sales during the POI as well as the injury period. The landed value of imports (as per DGCI&S data) are below the cost of sales and the domestic industry's selling price is below the landed value of imports. This indicates that the prices of the Domestic Industry are suppressed and depressed. However, the fact that the other producer holds a major market share is also important in deciding the prevailing market prices in turn affecting the prices of domestic industry.

**IV. Economic Parameters of the Domestic Industry**

82. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic

prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

83. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

**a. Market share:**

84. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

SN	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
1	Total Domestic Sale	MT	714,590	711,152	717,909	750,041
1a	Domestic Sales-Applicants	MT	228,540	248,652	270,509	293,341
1b	Domestic Sales-Others	MT	486,050	462,500	447,400	456,700
1c	Trend	Indexed	100	100	100	105
2	Imports from Subject Countries	MT	8,411	24,876	44,409	50,186
3	Imports from Other Countries	MT	2,584	3,780	4,224	5,934
4	Total Imports	MT	10,995	28,656	48,633	56,120
5	Total Demand	MT	725,585	739,808	766,542	806,161
5a	Trend	Trend	100	102	106	111
6	Market share in Demand					
6a	Of (Total)Domestic Sales	%	98.48	96.13	93.66	93.04
6b	Of DI Sales		31.49	33.61	35.28	36.38
6c	Of Imports from Subject countries	%	1.16	3.36	5.79	6.23
6d	Of Imports from Other Countries	%	0.36	0.51	0.55	0.74

85. The imports of the subject goods from subject countries have increased significantly from base year to POI in absolute terms. The total demand in India has shown a consistent increase, however, the market share of domestic sales (all producers) in total demand has decreased during POI as compared to the preceding years whereas market share of petitioners and imports from subject countries have increased during the same period.

**b. Profitability:**

86. The Domestic Industry stated that cost of sales has declined in the POI, as are the selling prices. It is seen that the selling price saw a substantial downward trend and the same consistently remained below the cost of sales of the Domestic Industry resulting into continued losses during the entire injury period. The Domestic Industry has also submitted that they were forced to match the post landing discounted prices offered by the exporters.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	92	78
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	94	79
Profit/Loss	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(124)	(68)	(71)

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
Profit/Loss	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(135)	(81)	(136)

87. The data indicates that the DI is suffering continued losses during the entire injury period and POI which is on account of selling price being lower than the cost of sales of DI. However, the other producer in India is holding a substantial share of the market and must also be held responsible for controlling the price structure along with the imports into the country.

**c. Return on Investment:**

88. The return on investment has seen significantly negative trend as can be seen from the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
ROI	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(265)	(190)	(319)

89. The domestic industry has increased its installed capacity and production continuously during the entire injury period and POI inspite of consistent negative ROI, therefore, the negative return on investment is not a conclusive indicator of adverse impact of injury due to dumping.

**d. Production and Capacity Utilization:**

90. It has been stated that the production of the Domestic Industry has increased in the POI as compared to the base year which is largely due to the fact that the demand has also increased. The domestic industry is operating at their full capacity, despite the fact that there has been a substantial increase in demand in the country.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI -A
Capacity	MT	441,102	497,862	504,450	505,110
Trend	Indexed	100	113	114	115
Total Production	MT	308,207	322,487	337,117	350,108
Trend	Indexed	100	105	109	114
Capacity Utilization	%	69.87	64.77	66.83	69.31
Trend	Indexed	100	93	96	99

91. The installed capacity of the domestic industry has increased during the entire injury period and POI when compared to the base year and previous years. The production of subject goods is also increasing during the entire injury period and POI which could be in response to the increase in demand. There is no indication of any adverse impact of injury due to dumping.

**e. Sales Volumes:**

92. It is noted that the sales volume of the Domestic Industry has increased in the POI as compared to the base year which is largely due to the fact that the demand in the country has increased. It is also noted that exports by DI have decreased, however, the present analysis has taken into account the analysis of domestic sales only, and therefore, the analysis is not impacted by the exports.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI -A
Domestic	MT	228,540	248,652	270,509	293,341
Trend	Indexed	100	109	118	128



Exports	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	91	76

**f. Inventories:**

93. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI-A
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	89	56

94. From the above, it is noted that the average inventory situation of the Domestic Industry has improved during the injury period indicating better market placement of the domestic industry hence do not indicate any adverse impact of injury due to dumping.

**g. Productivity, Employment and Wages:**

95. It has been stated that the number of employees engaged by the Domestic Industry decreased in the injury investigation period inspite of increase in production. The domestic industry has claimed that this is because they have to cut the costs to match the prices offered by the dumped imports. However, the wages paid to them has increased during the POI

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI -A
Production (MT)	MT	308,207	322,487	337,117	350,108
Employees	Number	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	98	62
Production/employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	112	123
Wages/employee	Rs. /Employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	117	190

96. It is noted from the above table that the production and productivity per employee has improved during the injury period and POI. The increase in productivity per employee indicates better efficiencies and increase in wages could be in response to the progressive state of normal market conditions with time and hence do not indicate any adverse impact of injury due to dumping.

**h. Magnitude of Dumping and Dumping Margin:**

97. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin determined against subject countries is above *de minimis* and significant.

**i. Growth:**

98. There was positive growth of the domestic industry in terms of production and sales in the POI as compared to the base year. However, profits, cash profit as well as ROI remained negative in the POI as compared to the preceding years despite significant increase in demand. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the presence of the dumped imports from subject countries at non-remunerative prices.

**j. Factors Affecting Domestic Price**

99. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. Even though Domestic Industry holds a major share of the market, they claim that import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. However, the fact that the other Indian producer, who holds a major market share, is also an extremely important player impacting the market prices of the subject goods. The information given by the user industry shows that the prices of M/s Reliance Industries Ltd. (non-petitioner producer) are consistently higher than the import prices and still they hold majority share of Indian demand. It is noted that the landed value of subject goods from subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed value of PUC from subject countries had suppressed / depressed the prices of the Domestic Industry causing financial losses to them. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries are minor in quantities and not injuring the domestic industry as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increase trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry. In view thereof, the imports and supplies of the other producer (non-petitioner producer), are shaping the price structure of the subject goods of domestic industry in India.

**H. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK**

100. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Rules and Agreement on Anti-dumping, the Authority proceeded to see whether any factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

**a. Volume and prices of imports from third countries**

101. During POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries are not significant in volume and were reported at high prices. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

**b. Contraction in demand:**

102. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

**c. Changes in the pattern of consumption: -**

103. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone material change and therefore could not have been the cause for the injury suffered by the domestic industry.

**d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: -**

104. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**e. Developments in technology: -**

105. The Authority also notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury to the domestic industry.

**f. Export performance:**

106. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

**g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry:**

107. Claimed injury to the domestic industry has been analysed on account of product under consideration only. Therefore, performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the present injury analysis.

**h. Other Producers in India**

108. There is another major producer of subject goods in India who has not joined the petition. However, the evidence available on record indicates that it plays a very significant role in deciding the market prices of the subject goods.

**I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

109. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

SN.	Producer	Exporter	Landed Value	NIP	Injury Margin		
			USD/ MT	USD/ MT	USD/ MT	%	Range
	CHINA PR						
1	M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China	1. M/s Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co. Ltd., China 2. M/s United Raw Material PTE Ltd	***	***	***	***	5-15
3	M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.,	M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd.,	***	***	***	***	5-15
4	M/s Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd.	1. M/s Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. 2. M/s Xiamen MC Group (HK) Corp. Ltd., 3. M/s United Raw Material PTE Ltd.	***	***	***	***	10-20
7	M/s Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd.	M/s Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
	INDONESIA						
8	Pt. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia	Pt. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia	***	***	***	***	1-10
	THAILAND						
9	Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand	Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., Thailand	***	***	(***)	(***)	(5)-5
	MALAYSIA						
10	M/s Recron Malaysia Sdn Bhd.	M/s Recron Malaysia Sdn Bhd.	***	***	***	***	5-15

**J. POST DISCLOSURE COMMENTS**

110. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

**Submissions made by the Domestic industry**

111. The Domestic Industry made the following submissions:

- a. Demand as well as market share have to be examined in the context of the entire market and not only for the Domestic Industry. It is, therefore, clear that market share as a factor of injury is also showing injury to the Domestic Industry as the share of all the domestic producers has fallen.
- b. The prices of PSF in the domestic market are determined on an import parity basis. The market is extremely competitive internationally and it is not possible for any producer in India, small or major, to fix its prices without consideration of the international prices at which the goods can be imported into India. The pricing dynamics remain the same for the petitioner companies as well as the non-petitioner companies as they are essentially competing in the same market under exactly the same conditions. The landed value of the subject goods is suppressing depressing the prices of the Domestic Industry, causing losses to them and exactly the same mechanism is in place even for the non-petitioner producer.
- c. The imports constitute only about 7% of the total demand, has no bearing on the fact that the prices in the domestic market are determined on the basis of the import prices. The imports constitute more than 14% in relation to domestic production in the country which is sufficient to influence the prices in the market.
- d. The negative rate of return is a function of lower price realization and is in no way connected with the fact that the installed capacity and production have gone up.
- e. As regards inventories and wages per employee, it appears that the figures for the POI have not been annualized which may kindly be corrected.

**Submissions made by the opposing interested parties**

112. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:

- a. The Authority may clearly clarify that “recycled PSF, non dyed or coloured are excluded from the scope of PUC”. It may also be made a part of duty table note so as to avoid any confusions at the end of customs authorities at the time of clearance of the material if the Authority recommends any duty in this matter.
- b. M/s PT Indorama Petrochemicals, Indonesia is related to the applicant by virtue of having common control as defined under the Companies Act 2013 as evident from the Annual Report of the applicant for the year 2016-17. Therefore, it is essential for the Authority to lift the veil of corporate cross ownership among the Lohia family members who are the beneficial owners of the Indorama Group in India as well as the subject countries.
- c. Non-consideration of RIL as domestic industry will certainly result in material risk of distortion of injury. It is a major producer of PUC in India and the focus of RIL continues to be on production of PUC and it has not shifted its focus to trading in the imported PUC. The small volume of PUC exported by Recron during the POI has been used for captive consumption by the mills. RIL cannot be said to have unduly benefited from dumping and hence its exclusion had to be examined by the Authority in terms of Article 4.1(i) of the Anti-Dumping Agreement.
- d. The Authority has failed to comply with the findings made by the Hon’ble High Court of Madras Order dated 20 November 2017 since no examination/analysis had been undertaken to determine that the effect of the relationship of RIL with Recron is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers. Moreover, Rule 2(b)(1) of the Rules is the enacting part and contains a deeming as to when exporters or importers are related. There has to be further reason to believe that the parties had factually exercised restraint in the course of dealings.

- e. The PDF/hard copy of the import data cannot be regarded as sufficient evidence for the allegation of imports.
- f. The domestic industry considered the various import transactions in the IBIS import data with the same or similar description both as PUC and as well as NPUC by defying all logics and principles of consistency and fairness and also concealed the complete product description in the various import transactions.
- g. M/s Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd. requested the Authority to determine the normal value on the basis of their records instead of constructing the normal value. It is further submitted that the Authority may also consider the information from Thailand for the determination of normal value for the Chinese exporters. With regard to the determination of constructed normal value, it is requested to consider raw material prices for PTA and MEG on the basis of average monthly prices reported in PCI reports details of which have already been provided vide our earlier submissions. The consumption norms for raw materials, other cost and profit may be taken on the basis of the information from Thailand producers participating in the current investigation.
- h. M/s Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co. Ltd has submitted that the authority has arbitrarily rejected their response on ground of incomplete value chain, however, none of the responding producer/exporter from china has provided complete value chain. It is further submitted that M/s Tionale Pte. Ltd. and M/s United Raw Material Pte Ltd. are unrelated independent companies, therefore, Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co. Ltd could not coerce or make it mandatory for unrelated traders to participate in the aforesaid anti-dumping investigation. The Authority must determine individual dumping margin for Xiamen Xianglu, based on its response to exporter's questionnaire response. In fact the authority must reject the response filed by united raw material PTE Ltd. since they have filed partial / incomplete exporter questionnaire response and concealed information concerning invoicing of goods exported by M/s Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co. Ltd.
- i. Several users/ downstream manufacturers/ industries/ associations have submitted that the domestic consumption of PSF in the manufacture of Man Made Fibre Textiles is 800,000 MT per annum. The structure of PSF manufacturing industry allows them to charge prices much higher than Import Parity Prices from the yarn spinning mills. Such prices are announced periodically disregarding the dynamics of demand and supply. This makes MMF yarn and fabrics more expensive, thereby restricting the growth of the MMF Textile Industry in India. Any further protection by way of anti-dumping duties will only make the domestic price of PSF more expensive-enriching handful of manufacturers at the cost of growth in the downstream industries. Higher cost of PSF in India will also encourage imports of yarn and fabric thereby halting the growth/closure along the value chain. ADD of Rs. 8 per Kg translates to Rs. 640 crores per year and Rs. 3200 crores over a 5 years' period. This anti-dumping will lead to imports of PSF stopping and being replaced by a much larger value of value added yarn, fabric and garments.
- j. The analysis with regard to imports in comparison to domestic production and domestic consumption has not been made.
- k. The reduction in cost of the domestic industry is on account of reduction in the prices of major raw materials i.e. PTA and MEG in the backdrop of declining crude oil prices which clearly indicates that there is no price depression since the costs of PTA and MEG consist of over 80% of the costs of the PSF. It is further submitted that the domestic industry has not passed on the full reduction in cost to its customers as it is visible from the significant decline in losses to the domestic industry by 36% over the injury investigation period. It clearly indicates that there is no price depression also in the current investigation.
- l. The mere existence of the parallel pricing trends during the injury investigation period between subject imports and domestic prices per se does not constitute sufficient evidence to demonstrate the existence of price effect as there may be other factors that have pushed down both the domestic prices and import prices.
- m. The total domestic sales include the sales of Reliance Industries whereas in Part II the applicants have claimed for exclusion of Reliance Industries from the purview of the domestic industry. It

clearly indicates that the domestic industry is making contradictory submissions and analysis with respect to standing and market share which ought not to be permitted.

- n. The domestic industry has made contradictory statements by stating, on one hand, that the domestic industry with a view to cut costs and to match the prices offered by the alleged imports reduced number of employees and whereas on the other hand it has been stated that the wages paid to the employees increased significantly by 23% over the injury investigation period. The computation of number of employees does not appear to be correct in the instant investigation since the applicant companies are multi-product companies. When the number of employees of the domestic industry was the highest in 2013-14, the wages were the least and when the number of employees was the lowest in POI, the wages were the highest. It clearly indicates that details of numbers of employees provided by the domestic industry are not correct and are misleading.
- o. The increased capacity in the recycled PSF industry also adversely impacted the PSF business. Sharing the same physical and chemical characteristics, recycled PSF is a powerful competitor of the products under consideration produced by the domestic industry.
- p. The domestic industry has failed to provide any evidence in support of their submission that the domestic industry was forced to match the post landing discounted prices offered by the exporters.
- q. The charging of higher prices in the domestic market by the applicant producers is also one more reason to indicate that they are in a position to dictate prices in the domestic market otherwise their sales in the export market could not have declined.
- r. The continued losses to the domestic industry are on account of the increase in cost due to the increase in depreciation cost, interest cost, wages cost, overheads etc. as result of the increase in the capacity of the domestic industry by 15% over the injury investigation period.
- s. The causal link analysis may be made for the whole industry after consideration of the available prices of Reliance Industries Limited and other domestic producers. The isolation of Reliance Industries Limited is not warranted even if it is excluded from the definition of the domestic industry. The impact of RIL dominance on the domestic prices and on the performance of the domestic industry ought to be distinguished and separated and not to be attributed to subject imports.
- t. Non-attribution examination of any other known factors also causing injury is also to be conducted and such injury ought not to be attributed to the subject imports.
- u. The NIP determined based on 22% as pre-tax return on average capital employed is highly inflated and is not based on real situations.

#### **Examination by the Authority**

113. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs. The PUC has been clearly defined and is not likely to cause any confusion. The issue of DI standing and relation between interested parties involved in the present investigation has been discussed threadbare and all the concerns have been addressed in the preceding relevant paragraphs. The NIP and cost of production for the PUC has been determined as per the Rules and the practices followed in the Directorate. The corrections in inventory and wages have been rectified to reflect the same for annualized POI. Other parameters of import volume and value have been examined on the basis of the data furnished by the co-operative exporters from Indonesia, Malaysia and Thailand. As for China the normal value has been constructed as detailed in above paras. M/s Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co. Ltd has not been granted individual dumping and injury margin in view of absence of complete information. The impact analysis of various related factors and non-attribution analysis has also been done in detail on the basis of information available in record. The extensive submissions made by the user industry regarding the comparative prices of the petitioner companies, non-petitioner (Indian) company and import prices of subject goods from subject countries have also been examined and analyzed appropriately.

#### **K. CONCLUSIONS**

114. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. Though the import of PUC has increased during POI as compared to base year, however, the quantum is not substantial as compared to total demand in India. The share of imports is only 7% which is not significant enough to cause material injury to DI.
- ii. The product under consideration has been exported to India from all the subject countries at dumped prices as compared to its normal value in the respective subject countries. However, the same are not solely responsible for causing material injury to the domestic industry as reflected by the analysis of various economic parameters.
- iii. The injury analysis indicates that the domestic industry is suffering on some of the economic growth parameters. However, it could also be on account of other factors which are beyond the scope of the present antidumping investigation.
- iv. The other producer in India, who has not joined the petition, holds the largest share of the demand and is playing a major role in the determination of prevailing prices of the subject goods as is clear from examination of the various submissions filed by the user industry.
- v. The detailed examination of the available material in the present case indicates that there is insufficient evidence to conclusively establish that dumping has caused material injury to the domestic industry. It is evident by the positive growth in domestic industry's production capacity, production, sale volume, market share etc.

### **RECOMMENDATION**

115. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules; it is established that the alleged imports are not solely responsible for causing material injury to the Domestic Industry. The Authority is of the view that imposition of antidumping duty is not warranted in the present investigation. Therefore, the Authority considers it appropriate to recommend termination of investigation in terms of Rule 14(b) of the Rules.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Designated Authority